नई दिल्ली
सोमवार
07 सितंबर 2026
वर्षः 13, अंकः 04
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की

बिहार के आरा में गाड़ी संख्या 15483 महानंदा...पेज-05

DELHIN/2014/58158

धान खरीद के लिए पंजाब कैबिनेट की तीन नीतियों...पेज-08

एक नजर

राष्ट्रपति मुर्मु ने देश के 8 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किये

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आठ उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, पंजाब और हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, पटना, कलकत्ता और बांबे उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त का आदेश दिया है। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के जज जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय के जज जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा को इसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के जज जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के जज जस्टिस वी कामेश्वर राव को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बांबे उच्च न्यायालय के जज जस्टिस आरवी घुगे को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी को बांबे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

ऑपरेशन तूफ़ान: केरल में 10,883 लोग गिरफ़्तार, 10,070 मामले दर्ज

तिरुवनंतपुरम,एजेंसी। केरल पुलिस के मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ़ चल रहे अभियान 'ऑपरेशन तूफ़ान' के तहत अब तक पूरे राज्य में 10,883 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और 10,070 मामले दर्ज किए गए हैं। ये गिरफ़्तारियां अभियान के हिस्से के तौर पर राज्य भर में अलग-अलग जगहों पर की गई जांच के दौरान हुईं। पिछले दिन 34 मामलों में 39 और लोगों की गिरफ़्तारी के साथ ही 'ऑपरेशन तूफ़ान' के तहत दर्ज मामलों की कुल संख्या बढ़कर 10,070 हो गई है। पुलिस ने अब तक इस ऑपरेशन के तहत 23,438.746 ग्राम एमडीएमए , 1,214.354 किलोग्राम गांजा और 4,738.269 ग्राम हशीश ऑयल ज़ब्त किया है। पिछले दिन दर्ज मामलों में से 12 मामले कम मात्रा में नशीले पदार्थ रखने से जुड़े थे, एक मामला मध्यम मात्रा और दो मामले कमर्शियल मात्रा से है। इसके अलावा, 19 मामले स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत और 25 मामले सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के तहत दर्ज किए गए। इन मामलों में ज़ब्त की गई चीज़ों में 1,995.470 ग्राम एमडीएमए, 1.176 किलोग्राम गांजा और 0.1 ग्राम हशीश ऑयल शामिल है। केरल पुलिस ने 'ऑपरेशन तूफ़ान' के तहत अकेले पिछले दिन राज्य भर में 12 जागरूकता कक्षायें आयोजित कीं। अब तक, 9,529 जागरूकता कक्षा और 649 काउंसलिंग सेशन आयोजित किए जा चुके हैं। स्कूल और कॉलेज सुरक्षा समूह की अगुवाई में 6,698 और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आम लोग मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी सीधे पुलिस को मोबाइल नंबर पर या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि इन नंबरों के ज़रिए जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

सत्य निकेतन हादसे में पांच लोगों की मौत, बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी

☐ दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश

नई दिल्ली,एजेंसी। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में रविवार दोपहर 1.30 मिनट पर (पीजी) इमारत गिरने के बाद एम्स ट्रॉमा सेंटर में लाए गए हादसे में घायल 10 लोगों में से पांच की मौत हो चुकी है। चार का इलाज चल रहा है। एक घायल को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। इमारत के मलबे में कई अन्य छात्रों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर व्यापक स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल से बात कर जमीनी हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ मिलकर तेजी से बचाव कार्य कर रहे हैं। घायलों को हर जरूरी मेडिकल मदद दी जा रही है। उन्होंने सभी घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने हादसा स्थल का दौरा करके सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि तालमेल बिठाकर काम करें और मौके पर तेजी से बचाव कार्य सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क कर स्थिति की जानकारी ली और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री स्वयं सत्य निकेतन स्थित घटनास्थल पर पहुंचीं और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बचाव अभियान की स्थिति की निगरानी की। उन्होंने निर्देश दिए कि मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए और राहत एवं बचाव कार्य में कोई कमी न रहे। मुख्यमंत्री घायलों के उपचार की जानकारी लेने एम्स ट्रॉमा सेंटर भी पहुंचीं। घटनास्थल पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), एनडीआरएफ, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), कैट्स और सिविल डिफेंस की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। सभी संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ युद्धस्तर पर राहत व बचाव अभियान चला रही हैं। सावधानी के दृष्टिगत घटनास्थल से सटे भवन को खाली करा लिया गया है। प्रशासन का पूरा ध्यान फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और प्रभावित परिवारों को तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर है।

मुख्यमंत्री लगातार क्षेत्रीय जिलाधिकारी, दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्थानीय सांसद बांसुरी स्वराज और आरके पुरम के विधायक अनिल शर्मा से भी बातचीत कर घटनास्थल की स्थिति और बचाव अभियान की जानकारी ली। सभी घटनास्थल पर भी पहुंचे। इस अत्यंत दुखद घटना में घायल छात्रों व अन्य लोगों के उपचार और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी लेने एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचीं। उन्होंने वहां चिकित्सकों से घायल छात्रों की स्थिति और उनके उपचार के संबंध में जानकारी ली। सभी घायल एम्स के चिकित्सकों की देखरेख में हैं और उनका उपचार जारी है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों की टीम को घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार घायल छात्रों के परिवारों के संपर्क में है और उन्हें आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी घायल छात्रों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने सत्य निकेतन हादसे के संबंध में स्पष्ट किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मकान मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं।

कांग्रेस ने सरकार पर लगाया इसरो की भूमिका सीमित करने का आरोप, रमेश बोले- वैज्ञानिकों की मेहनत को निजी क्षेत्र को सौंपने चिंता की बात

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के नाम पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की भूमिका सीमित कर रही है। उन्होंने कहा कि छह दशकों में वैज्ञानिकों और इसरो कर्मचारियों की मेहनत से विकसित क्षमताओं को निजी क्षेत्र को सौंपने की प्रक्रिया गंभीर चिंता का विषय है।

जयराम रमेश ने रविवार को एक्स पर एक अखबार की कटिंग साझा की, जिसमें इसरो के नौ कर्मचारी संगठनों की ओर से निजीकरण को लेकर उठाए गए सवालों का उल्लेख है। साथ ही उन्होंने राज्यसभा में इसी मुद्दे पर दिए अपने पुराने राज्यसभा भाषण का वीडियो भी साझा किया। इसमें उन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम के सार्वजनिक स्वरूप और वैज्ञानिक संस्थानों की स्वतंत्रता पर जोर दिया था।

जयराम रमेश ने कहा कि इसरो समुदाय के भीतर से निजीकरण को लेकर आवाज उठना सराहनीय है। उन्होंने हालिया जीएसएलवी प्रक्षेपण की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह इसरो की क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक पूर्व इसरो अध्यक्ष ने भी निजीकरण को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखी हैं और अन्य वैज्ञानिकों को भी चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अंतरिक्ष कार्यक्रम में आक्रामक निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। रॉकेट विकास और निर्माण में इसरो की भूमिका सीमित करने तथा उपग्रह संबंधी संसाधनों को निजी कंपनियों को हस्तांतरित करने की तैयारी है। उन्होंने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में बन रहे नए अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र और श्रीहरिकोटा के भविष्य को लेकर भी सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब इसरो को कमजोर करना नहीं होना चाहिए। इसरो देश की वैज्ञानिक विरासत है और भारत अपनी वैज्ञानिक रीढ़ के साथ समझौता नहीं कर सकता।

बिहार के घायल छात्रों से मिले राहुल गांधी, साथ खड़े रहने का किया वादा

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुए युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इन छात्रों ने सिर्फ शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही मांगी थी, लेकिन उनके साथ गोलीबारी कर दी गई। राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में वह यहां अपने आवास पर बिहार के तीन घायल छात्रों से बातचीत करते दिख रहे हैं।

इन छात्रों के नाम मोहम्मद आरिफ, बुलेट कुमार गौड़ और आकाश कुमार हैं। इनमें से बुलेट कुमार गौड़ के पैर में गोली लगी है और वह बैसाखी के सहारे चल रहा है। दो अन्य छात्रों के कंधे में गोली लगी है। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा, 'सोचिए, ऐसा क्या गुनाह किया था इन बच्चों ने कि इन्हें गोली मार दी गई? इन्होंने सरकार से सिर्फ तीन चीजें शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही मांगी थी।एक छात्र के पैर की हड्डी एके-47 की गोली से टूट गई। सेना में जाकर देश की सेवा करने का उसका सपना भी उसी के साथ चला गया। दो और छात्रों के कंधों को गोली चीरती हुई निकल गई। ये अपराधी नहीं थे। ये गरीब घरों के वो बच्चे थे जो अपने परिवार के सपने लेकर पढ़ने निकले थे - किसी को अच्छी नौकरी चाहिए थी, किसी को अपने घर के हालात बदलने थे। वीडियो में राहुल गांधी छात्रों से बातचीत करते दिखते हैं। वह छात्रों की हालत पूछते हैं और उनकी चोटों को देखते हैं। एक छात्र बताता है कि वह सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन गोली लगने से उसका सपना टूट गया।

ब्रिक्स सम्मेलन की वजह से जीएसटी परिषद की बैठक अब 7 अक्टूबर को होगी

नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 12 सितंबर को होने वाली 57वीं बैठक अब नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण स्थगित कर दी गई है। यह बैठक अब सात अक्टूबर को होगी।

आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक अब सात अक्टूबर को होगी। इससे पहले पांच और छह अक्टूबर को अधिकारियों की बैठक होगी। यह बदलाव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण किया गया है। पहले जीएसटी परिषद की बैठक 12 सितंबर को होने वाली थी, जो अब 7 अक्टूबर को होगी। भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन में पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक प्रभाव सहित कई महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ब्रिक्स के देशों में पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे।

नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो में आम यात्रियों के बीच पहुंचे, बच्चों को दी जीवनी पढ़ने की सीख

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को लोक कल्याण मार्ग से मेट्रो यात्रा के दौरान आम सह-यात्रियों, स्कूली बच्चों और युवाओं से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर साझा एक वीडियो में अनौपचारिक बातचीत में जहां एक तरफ शिक्षक दिवस और देश की प्रगति का जिक्र हुआ, वहीं प्रधानमंत्री ने छात्रों को किताबों से जुड़ने और जीवनियां पढ़ने की खास सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र काशी (वाराणसी) में हुए बदलावों को लेकर भी यात्रियों से सीधा फीडबैक लिया।

सफर के दौरान बच्चों और युवाओं से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि क्या वे देश की प्रगति पर चर्चा करते हैं और सामान्य किताबों के अलावा कुछ पढ़ते हैं। एक छात्र द्वारा सिर्फ उपन्यासों के अध्ययन की बात कहने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जीवनियां पढ़ने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा, 'कोशिश करनी चाहिए कि ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ें। आप किसी खिलाड़ी की, किसी सिने कलाकार की या किसी वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ सकते हैं... किसी की भी पढ़िए।' उन्होंने वहां मौजूद एक छात्र से पाठ्यक्रम से इतर ऐसी प्रेरक पुस्तकें पढ़ने का (संकल्प) भी लिया। इसी दौरान एक छात्र ने प्रधानमंत्री के सम्मान में 'गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुः...' श्लोक भी सुनाया, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका उत्साहवर्धन किया। बीएचयू से स्नातक और दिल्ली विश्वविद्यालय से वकालत (लॉ) करने वाली एक काशी की महिला यात्री से प्रधानमंत्री ने उनके संसदीय क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व बदलावों और जमीनी हकीकत की जानकारी ली।

राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ जीतेंद्र मिश्रा के नाम से वायरल शराब पीकर नाचने का वीडियो फर्जी

नवंबर 2025 का निकला

नई दिल्ली,एजेंसी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त पूर्णकालिक सीईओ सेवानिवृत्त एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल किया जा रहा एक वीडियो फर्जी निकला है। वीडियो में एक व्यक्ति शराब की बोतल या गिलास सिर पर रखकर उत्साह में नाचता दिखाई दे रहा है। दावा किया गया कि राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ नियुक्त होने के बाद जीतेंद्र मिश्रा शराब पीकर पार्टी कर रहे हैं।

हालांकि, जांच में सामने आया कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति जीतेंद्र मिश्रा नहीं है और यह वीडियो उनकी नियुक्ति से करीब 10 महीने पहले नवंबर 2025 में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। फैक्ट चेक सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने गलत व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के रूप में पेश किए जाने पर आपत्ति जताई। कुछ यूजर्स ने अयोध्या पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी कार्रवाई की मांग की। एक पोस्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि वीडियो में नाच रहा व्यक्ति राम मंदिर के सीईओ नहीं है और फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रश्मि नाम के एक्स हैंडल ने साझा किया। पोस्ट में लिखा गया, 'पहले चंदा गिनने वाले चोरी करते थे, अब सीईओ पार्टी मना रहा है। मंदिर को कॉर्पोरेट बना दिया भाई, डांस फ्लोर भी लग गया।' पोस्ट के साथ दावा किया गया कि वीडियो में जीतेंद्र मिश्रा को शराब पीते और नाचते हुए देखा जा सकता है। उपलब्ध सोशल मीडिया रिकॉर्ड के मुताबिक इस पोस्ट को काफी संख्या में लोगों ने देखा और साझा किया। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) सोशल मीडिया अभियान के संस्थापक अभिजीत दिपके के एक्स हैंडल से भी वीडियो को साझा किया गया। दिपके ने वीडियो

वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम अल अलामीन इंटरनेशनल एयर शो के लिए मिस्र पहुंची

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम, अल अलामीन इंटरनेशनल एयर शो में हिस्सा लेने के लिए मिस्र पहुंच गई है। दुनिया की इकलौती पांच हेलीकॉप्टरों वाली भारत की यह सारंग टीम 08 से 10 सितंबर तक होने वाले एयर शो में कोरियोग्राफ की एक सीरीज के जरिए अपनी सटीकता, प्रोफेशनलिज्म और उड़ान स्किल्स दिखाएगी। यह भारतीय वायुसेना की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों में एक और अहम मील का पत्थर है, जो भारत और इजिप्ट के बीच बढ़ते रक्षा और डिप्लोमैटिक संबंधों को दिखाता है।

देश में डिजाइन और बनाए गए एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) ध्रुव को उड़ाते हुए सारंग टीम अपने मुश्किल फॉर्मेशन मैनूवर, पास-पास उड़ान और सिंक्रोनाइज्ड हवाई सीक्वेंस के लिए मशहूर है। यह डिस्प्ले न केवल इसके पायलटों के असाधारण कौशल और अनुशासन को दिखाता है बल्कि भारत के स्वदेशी एयरोस्पेस उद्योग की क्षमताओं को भी दिखाता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सारंग टीम अपना मशहूर 'डॉल्फिन लीप' मैनूवर दिखाएगी और स्पॉट स्टॉल टर्न नाम का एक नया युद्धाभ्यास भी पेश करेगी। इस इंटरनेशनल एयर शो में टीम के हिस्सा लेने से दुनिया भर के दर्शकों और एविएशन के शौकीनों को एएलएच ध्रुव की वर्सेटिलिटी और फुर्ती देखने का मौका मिलेगा। अल अलामीन इंटरनेशनल एयर शो दुनिया भर की बड़ी एयरफोर्स के साथ-साथ एयरोस्पेस, डिफेंस और स्पेस सेक्टर के प्रोफेशनल्स को एक साथ लाएगा। मिस्र के आसमान में सारंग का डिस्प्ले इस इवेंट में एक खास डायमेंशन जोड़ने के साथ ही दुनिया भर की दूसरी इंटरनेशनल टीमों के साथ रिश्ते भी मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना की यह एरोबेटिक एयर डिस्प्ले टीम औपचारिक रूप से 2005 में 151 हेलीकॉप्टर यूनिट के रूप में स्थापित पांच संशोधित एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टरों का संचालन करती है। टीम का मुख्यालय तमिलनाडु के कोयंबटूर के पास सुलूर वायुसेना स्टेशन पर है।

टीम का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 2004 में सिंगापुर में एशियाई एयरोस्पेस शो में हुआ था। इस टीम ने द्विवार्षिक रक्षा हवाई शो सह प्रदर्शनी एयरो इंडिया, वायुसेना दिवस और नौसेना सप्ताह समारोह और राष्ट्रीय महत्व के अन्य कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया है। फरवरी 2024 में टीम ने सिंगापुर एयर शो में प्रदर्शन किया, जो भारत के बाहर उसका दूसरा प्रदर्शन और 2004 में उद्घाटन प्रदर्शन के बाद पहला प्रदर्शन था।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्टार्टअप एवं इनक्यूबेशन नीति, 2026 पर प्रमुख उद्यमियों के साथ किया संवाद

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को दिल्ली स्टार्ट-अप एवं इनक्यूबेशन नीति, 2026 पर आयोजित विशेष गोलमेज बैठक में सहभागिता की। नई दिल्ली स्थित कार्यक्रम में प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा यूथ फॉर गवर्नेंस के सहयोग से आयोजित इस बैठक में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, देश के प्रमुख उद्योगपतियों, स्टार्टअप संस्थापकों, निवेशकों और उद्यमिता क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। बैठक का उद्देश्य दिल्ली स्टार्ट-अप एवं इनक्यूबेशन नीति, 2026 को और प्रभावी बनाने के लिए उद्योग जगत एवं स्टार्टअप समुदाय से प्रत्यक्ष सुझाव प्राप्त करना और दिल्ली में एक मजबूत तथा उद्यमशील इकोसिस्टम तैयार करना था। बैठक में 400 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित प्रावधान वाली दिल्ली स्टार्ट-अप एवं इनक्यूबेशन नीति, 2026 की प्रमुख व्यवस्थाओं, इसके क्रियान्वयन ढांचे और स्टार्टअप क्षेत्र के हितधारकों से अपेक्षित सहयोग व सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने दिल्ली में स्टार्टअप एवं इनक्यूबेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अपने अनुभव, सुझाव और व्यावहारिक विचार साझा किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप राजधानी में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है। उन्होंने दिल्ली को भारत की स्टार्टअप एवं इनोवेटिव राजधानी बनाने के सरकार के संकल्प को दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में प्रतिभाशाली युवा, मजबूत शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी क्षमता, बड़ा बाजार और देश के प्रमुख उद्योगों की मौजूदगी इसे स्टार्टअप एवं इनोवेशन के लिए एक स्वाभाविक केंद्र बनाती है। सरकार का उद्देश्य ऐसा अनुकूल और सक्षम वातावरण तैयार करना है, जहां युवाओं के नए विचारों को प्रोत्साहन मिले, इनोवेशन को सही मंच मिले, उद्यमियों को आवश्यक सहयोग मिले और स्टार्टअप नए रोजगार एवं आर्थिक अवसरों का सृजन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली स्टार्टअप व इनक्यूबेशन नीति, 2026 के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों और स्कूलों में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने सहित स्टार्टअप्स को आवश्यक सहयोग और अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार द्वारा ठोस पहल की जा रही है। दिल्ली सरकार स्टार्टअप संस्थापकों, निवेशकों, उद्योग जगत, शिक्षण संस्थानों और युवाओं के साथ मिलकर नीति निर्माण को अधिक सहभागी और परिणामोन्मुख बनाएगी।

उद्योग जगत के अनुभव और सुझावों को नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली स्टार्टअप व इनक्यूबेशन नीति, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज देश के उन प्रमुख स्टार्टअप संस्थापकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई, जिन्होंने दिल्ली से अपने स्टार्टअप की शुरुआत की और उसे बड़े स्तर तक पहुंचाया है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य अपने कार्यकाल में इनक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति के माध्यम से 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित एवं सहयोग प्रदान करना तथा इन स्टार्टअप्स के माध्यम से 4 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। बैठक में देश के प्रमुख स्टार्टअप फाउंडर्स, उद्योगपतियों, निवेशकों और उद्यमिता विशेषज्ञों ने सहभागिता की।

दिल्ली सरकार ने 2,000 से अधिक जब्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने लंबे समय से विभिन्न पुलिस थानों और उनके आसपास पड़े दो हजार से अधिक जब्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की है। इसके साथ ही आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला में पांच से अधिक लंबित पुलिस मामलों से जुड़े रासायनिक विश्लेषण का पूरा बैकलॉग समाप्त कर सक्रिय लंबित मामलों की संख्या शून्य कर दी गई है। इन दोनों कदमों का उद्देश्य वर्षों से लंबित प्रक्रियाओं को गति देना, सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और आबकारी कानून के प्रवर्तन को अधिक प्रभावी बनाना है। यह जानकारी रविवार को एक विज्ञप्ति के जरिए दी गई।

दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत जब्त किए गए दो हजार से अधिक वाहन लंबे समय से पुलिस थानों के बाहर और उनसे सटी सार्वजनिक भूमि पर खड़े हुए थे। इस समस्या के समाधान के लिए आबकारी विभाग ने दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत विशेष निस्तारण अभियान चलाया। इसके अंतर्गत जब्ती और सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए 2,000 से अधिक वाहनों की नीलामी की गई। इस कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और प्रशासनिक लाभ भी सामने आया है। समय रहते वाहनों की नीलामी से जब्त संपत्तियों के लगातार घटते मूल्य को रोकने में मदद मिली और सरकार को पांच करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। लंबे समय से पड़े वाहनों को हटाए जाने से पुलिस थाना परिसरों और सार्वजनिक भूमि पर घिरी जगह भी खाली हुई है। यह प्रक्रिया जारी है ताकि शेष जब्त वाहनों की व्यवस्थित रूप से पहचान कर आगे उनका निस्तारण किया जा सके। आबकारी विभाग ने समानांतर रूप से आबकारी नियंत्रण प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली में भी बड़ा प्रशासनिक सुधार किया है। प्रयोगशाला में पुलिस मामलों से संबंधित 5,000 से अधिक पुराने रासायनिक विश्लेषण मामले लंबित थे। विभाग ने इन सभी लंबित मामलों का निस्तारण कर सक्रिय बैकलॉग को शून्य कर दिया है। पहले जब्त शराब के नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त करने में वर्षों तक का समय लग जाता था। इस कारण संबंधित पुलिस जांच में काफी देरी होती थी और उसके बाद की कानूनी प्रक्रिया भी प्रभावित होती थी। इस स्थिति में सुधार के लिए लंबे समय से रिक्त पड़े पदों पर कर्मचारियों की भर्ती की गई है। रासायनिक जांच रिपोर्ट तेजी से मिलने का सीधा लाभ आबकारी कानून के प्रवर्तन और पुलिस जांच को मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार तेज जांच व्यवस्था से आबकारी प्रवर्तन क्षमता मजबूत होगी और अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ प्रभावी निवारक व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। समय पर रासायनिक जांच रिपोर्ट मिलने से पुलिस को जांच पूरी करने और समयबद्ध तरीके से आरोप-पत्र दाखिल करने में भी सहायता मिलेगी।

स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पिता पर हमला कर घायल करने के आरोपित स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज स्वतंत्र भारद्वाज की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट अंजलि सिंह की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को 5 सितंबर को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

स्वतंत्र भारद्वाज ने एक पॉडकास्ट में स्वीकार किया था कि उसने एक प्रदर्शनकारी छात्रा के पिता के सिर पर हमला किया। इस पॉडकास्ट के बाद काकरोच जनता पार्टी और कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब स्वतंत्र भारद्वाज ने खुद ही पॉडकास्ट में कबूल किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस प्रदर्शन के बाद स्वतंत्र भारद्वाज को बुलंदशहर में गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ पॉक्सो कानून और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

दिल्ली-एनसीआर में वर्षा होने से निचले इलाकों में भारी जलभराव

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली-एनसीआर में बीते दो दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। यहां लगातार बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कई कॉलोनियों और निचले इलाकों में जलभराव के कारण घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे भारी नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बारिश शनिवार को दिनभर रुक-रुक कर जारी रही। इसके चलते आईटीओ, आश्रम, धौला कुआं, रिंग रोड, विकास मार्ग और दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया। निचले इलाकों खासकर सीमापुरी, संगम विहार, बादली, मयूर विहार फेज-3 और नजफगढ़ के कई क्षेत्रों में घुटनों तक पानी जमा हो गया। जलभराव के खतरे को देखते हुए प्रशासन को एहतियातन कई प्रमुख अंडरपास पर बैरिकेडिंग कर यातायात बदलना पड़ा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को जाम से बचने के लिए जलभराव वाले रास्तों से दूर रहने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार मानसून की सक्रिय ट्रफ लाइन दिल्ली-एनसीआर के करीब से गुजर रही है, जिसके चलते यह मौसमी बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी में ऐसा ही मौसम सोमवार को भी बने रहने के आसार हैं। इस दौरान हल्की से मध्यम तथा कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना बनी रहेगी। लगातार हो रही बारिश होने से हवा की गुणवत्ता (एक्यूआई) में भी बड़ा सुधार देखा गया है। पूरे राजधानी में नगर निगम (एमसीडी) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कर्मचारियों को पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट के साथ फील्ड में तैनात किया गया है।

शाहदरा में एक करोड़ की हेरोइन बरामद, तस्कर गिरफ्तार

नई दिल्ली। शाहदरा जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान रॉकी उर्फ प्रदीप (35) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 282 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद की है। इसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। उसके पास से एक स्कूटी भी बरामद हुई है। पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा के मुताबिक, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल एक आरोपित सीमापुरी स्थित दिल्ली जल बोर्ड के पास डियर पार्क इलाके में आने वाला है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दी। कुछ देर बाद एक युवक स्कूटी से वहां पहुंचा। पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके पास से एक पैकेट में 282 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने रॉकी उर्फ प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह यमुनापार के अलावा दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हेरोइन की आपूर्ति करता है। शुरुआती जांच में पता चला है कि उसे बरेली से हेरोइन मिलती थी। आरोपित के मुताबिक, सीमापुरी में ही उसका सप्लायर उसे मादक पदार्थ उपलब्ध कराता था। पुलिस अब आरोपित के सप्लायर का पता लगाने में जुटी है। यह भी जांच की जा रही है कि बरेली से हेरोइन की खेप किसके जरिए सीमापुरी तक पहुंचती थी और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, रॉकी के खिलाफ पहले से मादक पदार्थ तस्करी के चार मामले दर्ज हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

शाहदरा में एक किशोरी ने की आत्महत्या

नई दिल्ली,एजेंसी। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में देर से घर लौटने पर परिजनों की डांट से आहत होकर 13 वर्षीय एक किशोरी ने कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतका मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली थी और शाहदरा में अपने परिवार के साथ रहती थी। शनिवार को वह किसी काम से बाहर गई थी और घर देर से लौटी। देर से आने पर परिजनों ने उसे कड़ी डांट लगा दी थी। डांट से क्षुब्ध होकर किशोरी कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब उसकी बहन कमरे में पहुंची, तो उसने उसे फंदे से लटकते देखा। बहन के शोर मचाने पर परिजन तुरंत कमरे में पहुंचे और किशोरी को फंदे से नीचे उतारा। इस बीच मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो किशोरी फर्श पर अचेत अवस्था में थी। उसे तत्काल नजदीकी डॉ. हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में परिजनों की फटकार से आहत होकर आत्मघाती कदम उठाने की बात सामने आई है। फिलहाल, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले से संबंधित जांच शुरू कर दी गई है।

आई-ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक निवेशक होंगे शामिल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को आयोजित होने वाले पहले आई-ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, पेंशन फंड और परिवार कार्यालय (फैमली ऑफिस) हिस्सा लेंगे। आयोजकों ने शनिवार को बताया कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक ट्रिलियन डॉलर (1,000 अरब) अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल सॉवरेन कैपिटल समिट का आयोजन होगा। इस आई-ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, पेंशन निधियां और पारिवारिक संपत्ति प्रबंधन संस्थाएं शामिल होंगीं।

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को दो दिवसीय 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका मकसद ब्रिक्स के 21 सदस्य एवं साझेदार देशों में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता से जुड़ी बैंक योग्य परियोजनाओं के लिए संप्रभु पूंजी और निवेशकों के बीच संपर्क को स्थापित करना है। 'सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट' (एसडब्ल्यूएफआई) ने एक बयान में कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय में होने जा रहा है, जब ब्रिक्स की अर्थव्यवस्थाएं बदलती व्यापार परिस्थितियों, अमेरिका की शुल्क नीतियों और डॉलर में लेनदेन की बढ़ती लागत जैसी चुनौतियों के बीच अपनी रणनीतियों को बदल रही हैं। एसडब्ल्यूएफआई के अनुसार सम्मेलन में भारत के एकीकृत पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और ब्राजील के पिक्स जैसे राष्ट्रीय त्वरित भुगतान नेटवर्क को जोड़ने के साथ केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) के बीच अंतर-संचालन की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी। उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स दुनिया के प्रमुख उभरते हुए बाजारों और विकासशील देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। पहले इसमें पांच देश शामिल थे लेकिन विस्तार के बाद अब इसमें 11 सदस्य देश हैं। इस संगठन के नाम की उत्पत्ति शुरुआती 4 देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) के अंग्रेजी नामों के पहले अक्षरों से इसे पहले 'ब्रिक' नाम दिया गया था, जो वर्ष 2011 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने पर ब्रिक्स बन गया। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। इसके सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, और वैश्विक राजनीतिक व आर्थिक शासन में सुधार करना है। अभी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब और इंडोनेशिया इसके सदस्य देश हैं।

मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग विधानसभा में कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को शालीमार बाग विधानसभा में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था, पार्कों के सौंदर्यीकरण और सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग स्थित बीबी-ब्लॉक की स्कूल बिल्डिंग के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। वहीं, विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एएफ-ब्लॉक में खुले ओवरहेड कंडक्टर को अंडरग्राउंड केबल में बदलने के कार्य का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग के सीएंडडी ब्लॉक की मेन रोड पर खुले ओवरहेड कंडक्टर को अंडरग्राउंड केबल में बदलने के कार्य का शुभारंभ किया। इससे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने पीतमपुरा स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से रिंग रोड तक नई सड़क के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। लगभग 2.84 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के साथ-साथ नागरिकों के आवागमन को अधिक सुविधाजनक बनाएगी। उन्होंने हैदरपुर के नेहरू कैंप में नवनिर्मित टॉयलेट ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। साथ ही पीतमपुरा के एसपी-टीपी ब्लॉक में आधुनिक कॉम्पैक्टर का उद्घाटन किया। आधुनिक कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह पहल क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने वाईपी ब्लॉक के तीन और डब्ल्यू पी ब्लॉक के 10 पार्कों में होने वाले सौंदर्यीकरण व विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इन कार्यों के माध्यम से स्थानीय निवासियों को बेहतर, स्वच्छ और सुंदर हरित क्षेत्र उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य विकास को केवल बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित न रखकर हर गली, हर कॉलोनी और हर नागरिक तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना है। सरकार स्वच्छता, हरित व सुंदर सार्वजनिक स्थलों, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और मजबूत शहरी व्यवस्थाओं के माध्यम से दिल्लीवासियों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र को स्वच्छता, बेहतर जनसुविधाओं, सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं और मजबूत शहरी व्यवस्थाओं से युक्त एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करना दिल्ली सरकार का संकल्प है।

कोयला मंत्रालय ने पंजाब के बिजली संयंत्रों को अपर्याप्त कोयला आपूर्ति की खबरों को किया खारिज

नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें पंजाब के ताप विद्युत संयंत्र में बिजली उत्पादन में कमी के लिए केंद्र सरकार से अपर्याप्त कोयला आपूर्ति को जिम्मेदार ठहराया गया था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पंजाब के बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयला उपलब्ध कराया गया है। कोयला मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में बताया कि पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन में कमी का कारण केंद्र से कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति को बताने वाली मीडिया रिपोर्टें पूरी सच्चाई नहीं दर्शाती हैं। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) पंजाब राज्य सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब में स्वतंत्र बिजली संयंत्रों (आईपीपी) को कोयले की आपूर्ति में सक्रिय रूप से सहायता प्रदान की है। कोयला मंत्रालय ने दोहराया कि केंद्र सरकार ने पंजाब के आईपीपी को कोयले की आपूर्ति को पूरी सक्षम बनाने के लिए पहले ही ठोस कदम उठाए हैं, जिसमें पीएसपीसीएल की कैप्टिव खदानों से आपूर्ति की अनुमति देने के लिए वैधानिक अंतिम-उपयोग प्रतिबंधों में ढील देना शामिल है।कोयला मंत्रालय ने कहा कि पीएसपीसीएल तीन ताप विद्युत संयंत्रों का संचालन करती है, जिसमें गुरु हरगोबिंद ताप विद्युत संयंत्र (लेहरा मोहब्बत), गोइंदवाल साहिब ताप विद्युत संयंत्र और रोपड़ ताप विद्युत संयंत्र शामिल है, जिनकी संयुक्त क्षमता 2,300 मेगावाट है। 04 अगस्त, 2026 तक, पीएसपीसीएल के संयंत्रों में कोयले का भंडार मानक आवश्यकता का लगभग 117 फीसदी था, जो पर्याप्त से अधिक कोयले की उपलब्धता को दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि इस पर्याप्त भंडार के बावजूद अगस्त, 2026 के दौरान पीएसपीसीएल के संयंत्रों का औसत प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) केवल करीब 42 फीसदी था।

दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना का जागरूकता अभियान शुरू, मार्च 2027 तक चलेगा : सिरसा

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर और व्यापक प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में प्रवर्तन, तकनीकी हस्तक्षेप, हितधारकों की भागीदारी और जनसहभागिता को समाहित किया गया है। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने एक व्यापक शहरव्यापी सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) एवं जागरूकता अभियान शुरू किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए पूरी गंभीरता और निरंतरता के साथ कार्य कर रही है। सरकार हर स्तर पर प्रवर्तन को मजबूत कर रही है और व्यापक उपाय लागू कर रही है। लेकिन स्वच्छ हवा की लड़ाई केवल सरकार के प्रयासों से नहीं जीती जा सकती। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक संस्थान और प्रत्येक हितधारक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है।

सिरसा ने बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा संचालित यह अभियान सितंबर 2026 से मार्च 2027 तक 'साथ निभाएं, प्रदूषण घटाएं' थीम के तहत चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से दिल्ली के विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों, उद्योगों, समुदायों और नागरिकों को एकजुट करते हुए स्वच्छ और स्वस्थ वायु के लिए एक निरंतर एवं सामूहिक जनआंदोलन तैयार किया जाएगा। इसी उद्देश्य से यह अभियान पर्यावरण संबंधी जागरूकता को केवल जानकारी तक सीमित न रखते हुए उसे कार्रवाई में बदलने पर जोर देगा। इसके माध्यम से नागरिकों को प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों के बारे में जागरूक किया जाएगा और उन्हें सरल एवं व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी जाएगी, जिनके माध्यम से व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने में योगदान दे सकते हैं। आने वाले महीनों में दिल्लीभर में जागरूकता, संवेदनशीलता एवं हितधारक सहभागिता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। स्कूलों और कॉलेजों, उद्योगों, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए), बाजारों, निर्माण क्षेत्र से जुड़े हितधारकों, बल्क वेस्ट जेनरेटर्स, किसानों, वाहन मालिकों और आम नागरिकों को लक्षित गतिविधियों के माध्यम से अभियान से जोड़ा जाएगा। सिरसा ने कहा, 'हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है—विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी साथ-साथ चलनी चाहिए। उद्योग, संस्थान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान दिल्ली को स्वच्छ हवा दिलाने की यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। इस अभियान के माध्यम से हमारा उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, अनुपालन को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक हितधारक समझे कि सतत विकास और प्रदूषण नियंत्रण एक-दूसरे के पूरक उद्देश्य हैं। अभियान की शुरुआत विभिन्न विभागों और हितधारकों द्वारा की जा रही कई जमीनी स्तर की गतिविधियों के साथ हो चुकी है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपने स्वच्छता कर्मचारियों के साथ आईईसी गतिविधियां आयोजित कीं। वहीं, कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन चिंतन ने 'दिल्ली को कूड़े से आजादी - स्वच्छता अभियान 2026' के तहत लोधी गार्डन और चाणक्य मॉल में हाउसकीपिंग कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स सत्र आयोजित किए। परिवहन विभाग ने पीयूसी अनुपालन, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, समय पर वाहन सर्विसिंग, उपयोग की अवधि पूरी कर चुके वाहनों के जिम्मेदार निस्तारण, स्वच्छ ईंधन, इलेक्ट्रिक वाहनों और दिल्ली ईवी नीति पर केंद्रित जागरूकता गतिविधियां आयोजित कीं तथा परिवहन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को अभियान से जोड़ा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी 300 विद्यार्थियों की भागीदारी के साथ सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये गतिविधियां केवल शुरुआत हैं। आने वाले महीनों में दिल्ली सरकार पूरे शहर में जागरूकता, जनसंपर्क और हितधारक सहभागिता से जुड़ी गतिविधियों की एक सतत श्रृंखला आयोजित करेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदूषण नियंत्रण केवल सरकार का कार्यक्रम न रहकर समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी वाला सामूहिक जनआंदोलन बने।

एक नजर

सम्मेलन में कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर

नूंह,एजेंसी। नूंह जिले के पिनगवां में रविवार को कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन को ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत और सक्रिय किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करने तथा उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और कानून-व्यवस्था सहित जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं को जनता के बीच मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने पिनगवां में कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी को संगठन की मजबूती का संकेत बताया। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि कांग्रेस की ताकत उसके जमीनी और समर्पित कार्यकर्ता हैं।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी समय में बूथ स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा के विषयों को भी प्रमुखता से उठाने की बात कही। संजय दत्त ने कहा कि मेवात की धरती से उठने वाली बदलाव की आवाज को पूरे हरियाणा तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। सम्मेलन में कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न स्तरों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई।

दो बच्चों के साथ कुएं में कूदी महिला, दोनों मासूमों की मौत

नूंह। नूंह जिले के नगीना गांव में रविवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। करीब 30 वर्षीय महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। हादसे में दोनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि महिला को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, नगीना गांव निवासी आसिक की पत्नी समरीन ने अपने दो वर्षीय बेटे अजलान और चार वर्षीय बेटी समायरा के साथ कुएं में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

ग्रामीणों ने प्रयास कर तीनों को कुएं से बाहर निकाला। तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी, जबकि समरीन को जीवित बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए अल-आफिया अस्पताल, मांडीखेड़ा की मोर्चरी में रखवा दिया है। दो मासूम बच्चों की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, घटना के बाद गांव में भी मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीण इस घटना से स्तब्ध हैं। देर शाम तक मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई थी। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

सेवानिवृत प्रोफेसर से पुलिसकर्मी बनकर ठगे गहने, कीमत पांच लाख

गुरुग्राम। यहां सेक्टर-7 एक्सटेंशन में बाइक सवार दो युवकों ने मंदिर से लौट रही 65 वर्षीय रिटायर्ड प्रोफेसर को पुलिस वाला बनकर रोका और पांच लाख रुपये के सोने के कंगन ठग लिए। शिकायतकर्ता जगदीश चंद के अनुसार उनकी पत्नी सरला कुमारी आर्य समाज मंदिर में पूजा कर लौट रही थीं। मकान नंबर-904 के पास बाइक पर आए दो युवकों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए पहचान पत्र दिखाया। उन्होंने कहा कि आगे बदमाश घूम रहे हैं, चेकिंग चल रही है। आपके साथ चोरी हो सकती है, अपने कंगन उतार कर बैग में रख लो। महिला घबरा गई। ठगों ने उन्हें एक कागज दिया और कंगन उसमें लपेटने को कहा।

मदद के बहाने एक ठग ने कंगन अपने हाथ में ले लिए और कागज में लपेटने का नाटक कर नकली कंगन थमा दिए। महिला ने बिना चेक किए कागज पर्स में रख लिया। घर आकर पर्स खोला तो अंदर नकली कंगन निकले। महिला के पति जगदीश चंद ने बताया कि उन्होंने कंगन 2.38 लाख रुपये में खरीदे थे, जिनकी मौजूदा कीमत करीब पांच लाख रुपये है, जबकि पुलिस ने एफआईआर में कीमत 80 हजार रुपये दर्शाई है। जगदीश खुद दिल्ली में सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं। जांच अधिकारी रज्जक खान ने बताया कि शिकायत मिलते ही उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया। आंकी गई कीमत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, असली कीमत रिकवरी के बाद तय होगी। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

समूचे लोस क्षेत्र में घूम रहा विकास का पहिया : कृष्णपाल गुर्जर

फरीदाबाद,एजेंसी। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा है कि हमारा संकल्प है कि एनआईटी विधानसभा का कोई भी क्षेत्र विकास से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। श्री गुर्जर शनिवार सायं वार्ड नंबर-10, के 27 फीट रोड, डबुआ कॉलोनी, एनआईटी में आयोजित कार्यक्रम में करीब साढ़े 14 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करने के उपरांत उपस्थितजनों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधायक एनआईटी सतीश फागना तथा वार्ड नंबर-10 के पार्षद जय भगवान सिंह भी मौजूद रहे।

कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि क्षेत्र में जनसुविधाओं को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से इन कार्यों का शिलान्यास किया। इन विकास

कार्यों में आरसीसी नाले, आरसीसी रास्ते, नई पाइपलाइन, वार्ड पार्षद कार्यालय का निर्माण आदि कार्य शामिल हैं। इन कार्यों से क्षेत्रवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि एनआईटी विधानसभा में निरंतर विकास कार्य धरातल पर उतारे गए हैं। आज वार्ड नंबर 10 में लगभग साढ़े 14 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शुभारंभ किया जा रहा है, जिनमें सीवर, पेयजल पाइपलाइन, नालियाँ, टाइल वाली गलियाँ और आरएमसी सडक़ें शामिल हैं। एनआईटी विधानसभा के सभी नौ वार्डों में विकास कार्य लगातार चल रहे हैं। वर्ष 2027 तक सीधे यमुना से पाइपलाइन बिछाकर एनआईटी विधानसभा के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही पूरी विधानसभा में हाईटेंशन बिजली की तारों को भूमिगत करने का काम भी किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक सतीश फागना ने कहा कि वार्ड नंबर-10 में करीब साढ़े 14 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

नूंह में दुकान के बाहर सो रहे दुकानदार की मौत, हत्या की आशंका

नूंह,एजेंसी। नूंह जिले के सदर थाना फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के रावली गांव में रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब दिल्ली-अलवर रोड स्थित अपनी किराने की दुकान के बाहर टीन शेड के नीचे सो रहे 58 वर्षीय दुकानदार इदरीश कुरेशी का शव घायल अवस्था में मिला। मृतक के शरीर पर चोट के निशान और कान के पास गहरा जख्म मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।

मृतक की पहचान रावली गांव निवासी इदरीश कुरेशी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार इदरीश रोजाना दुकान बंद करने के बाद दुकान के बाहर बने टीन शेड के नीचे सोता था। शनिवार रात भी वह रोजाना की तरह दुकान बंद करने के बाद वहीं सो गया था। रविवार सुबह परिजन और आसपास के लोग नमाज के लिए उसे जगाने पहुंचे। काफी आवाज देने के बावजूद जब इदरीश ने कोई जवाब नहीं दिया तो परिजनों ने पास जाकर देखा। वह घायल अवस्था में मृत पड़ा था। उसके कान के पास गहरा जख्म और शरीर पर चोट के निशान देखकर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने इसे सामान्य मौत मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना फिरोजपुर झिरका प्रभारी सुभाष चंद्र पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से संभावित साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। सूचना मिलने पर फिरोजपुर झिरका के डीएसपी हरदीप सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।

गुरुग्रामः नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तीन दिन और बढ़ी

गुरुग्राम। हरियाणा में नगर पालिका कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल तेज हो गई है। संघ ने हड़ताल को तीन दिन और बढ़ाकर नौ सितंबर तक जारी रखने का फैसला लिया है। गुरुग्राम में पुराने नगर निगम कार्यालय पर 32वें दिन भी हड़ताल जारी रही। रविवार होने के कारण कर्मचारियों की धरने पर हाजिरी कम रही। रविवार को हड़ताल की अध्यक्षता इकाई कोषाध्यक्ष भारत कांगड़ा और फायर के जिला प्रधान जोगिंदर ने की, संचालन सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक सचिव महेश कुमार ने किया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि नौ सितंबर तक आदेश जारी नहीं हुए तो हड़ताल को अनिश्चितकालीन कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

सीटू के जिला प्रधान सुरेश नोहरा, तेजपाल और कैलाश जॉन समेत अन्य नेताओं ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य उप प्रधान बसंत कुमार ने कहा कि सरकार 13 मई को माने गए फैसलों के पत्र जारी नहीं कर रही है। जब तक पे-रोल के 1175 फायरमैन और पालिका रोल के 13000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने समेत अन्य मांगों के आदेश जारी नहीं होते, हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने सरकार पर पुलिस दमन और गिरफ्तारियों का आरोप लगाया। वरिष्ठ उप प्रधान सम्मी बोहत और फायर के जिला सचिव सुनील कुमार ने कहा कि 11 साल में सरकार ने एक भी सीवर और सफाई कर्मचारी की पक्की भर्ती नहीं की। सफाई कार्य को ठेके पर देकर कम वेतन में ज्यादा काम कराया जा रहा है।

जबकि 30 जून 2022 के पत्र के अनुसार अन्य विभागों के कर्मचारियों को एचकेआरएन में समायोजित किया जा चुका है, पालिका कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। संघ ने बताया कि 13 मई के समझौते में 17 मांगों पर सहमति बनी थी, जिनमें 30 जून तक सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, सफाई-सीवर का ठेका खत्म करना और बैंक के माध्यम से न्यूनतम वेतन 15,200 देन, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती, एक्स-ग्रेशिया, ग्रेच्युटी और पांच लाख सम्मान राशि, गुरुग्राम के 3480 सहित सभी छंटनीग्रस्त कर्मचारियों को वापस लेना, 5,000 रुपये जोखिम भत्ता और फायर कर्मचारियों को वर्दी भत्ता और शहीद कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख सहायता और नौकरी देना शामिल है।

नोएडाः अलग-अलग सड़क हादसों में छह की मौत

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में रविवार को हुए सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई। किसी की मौत मौके पर हुई तो किसी की इलाज के दौरान। संबंधित थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई पुलिस जुट गई है। थाना सेक्टर 63 के प्रभारी निरीक्षक अमित काकरान ने बताया कि गजेंद्र सिंह पुत्र सूरजपाल उम्र 36 वर्ष रविवार को साइकिल पर सवार होकर एफएनजी रोड से गुजर रहे थे, तभी एक स्कॉर्पियो कार के चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दिया। इस घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना फेस- दो के प्रभारी निरीक्षक राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में आज हुए एक सड़क हादसे में अशोक (40) पुत्र राम धीरज गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक हरीश

कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना दादरी के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में पंकज (36) पुत्र धीर सिंह मूल निवासी जनपद मेरठ गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनके उपचार के दौरान मौत हो गई। थाना जेवर के प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि अंकित शर्मा (39 वर्ष) पुत्र नारायण दत्त शर्मा निवासी ग्राम बनवारी बांस थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में बीती रात को गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी आज मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना दनकौर के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में मनोज (42) पुत्र राज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर उनकी मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार के दौरान आज उनकी मौत हो गई। थाना बादलपुर के प्रभारी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि सूरज चौहान (30) पुत्र राजपाल सिंह थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान उनकी आज मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना दनकौर के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में मनोज (42) पुत्र राज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर उनकी मौत हो गई।

फरीदाबाद : सुरक्षा ड्यूटी से 700 पुलिसकर्मी थानों में लौटाए जाएं- नीरज शर्मा

फरीदाबाद,एजेंसी। फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने हरियाणा में धमकी मिलने वाले लोगों की सुरक्षा में तैनात करीब 700 पुलिसकर्मियों को वापस बुलाने और थाने और चौकियों में लगाने की मांग की है। शर्मा का कहना है कि प्रदेश के कई थानों और चौकियों में पुलिसकर्मियों की कमी है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है और पुलिस से जुड़े काम करवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध और रंगदारी का डर बढ़ रहा है, लेकिन सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रही है। रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान नीरज शर्मा ने कहा कि गैंगस्टरों की धमकियों और रंगदारी मांगने की घटनाओं से व्यापारी और उद्योगपति डर के माहौल में हैं।

अगर कारोबारियों को सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलेगा तो दूसरे राज्यों से आने वाले उद्योगपति हरियाणा में निवेश करने से भी पीछे हट सकते हैं। उन्होंने सरकार से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पूर्व विधायक ने कहा कि, कांग्रेस की मुलाना विधायक पूजा द्वारा विधानसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न

संख्या 85 के जवाब में सरकार के आंकड़ों से प्रदेश में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की तस्वीर सामने आती है। उनके मुताबिक, एक जनवरी 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच गैंगस्टरों ने पूर्व जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, व्यापारियों और आम लोगों को धमकियां दीं। कई मामलों में जान से मारने की धमकी तक दी गई। नीरज शर्मा ने बताया कि उन्होंने पुलिस विभाग और पंचकुला पुलिस मुख्यालय से आरटीआई के जरिए धमकियों, सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों और उस पर हुए सरकारी खर्च की जानकारी मांगी थी। उनका आरोप है कि कई जिलों से अधूरी जानकारी दी गई। इससे उन्हें लगता है कि सरकार प्रदेश की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह सामने नहीं आने देना चाहती। पूर्व विधायक ने कहा कि जिन लोगों को वास्तव में खतरा है, उनकी सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसके लिए प्रदेश के थानों और चौकियों को कमजोर नहीं किया जा सकता। करीब 700 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा ड्यूटी और दूसरी तरफ थानों में स्टाफ की कमी पर सरकार को जवाब देना चाहिए उन्होंने मांग की कि पुलिस बल की समीक्षा कर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए लगाया जाए।

दिल्ली मेट्रो में रील बनाई तो खैर नहीं, रखी जा रही है नजर

गुरुग्राम। गुरुग्राम को समयपुर बादली से जोड़ने वाली येलो मेट्रो लाइन पर मेट्रो में व मेट्रो स्टेशनों पर रील बनाने के बढ़ते ट्रेंड को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने सख्त एडवाइजरी जारी की है। गुरुग्राम समेत एनसीआर के सभी स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इंस्टाग्राम पर इन दिनों एक नया रील चैलेंज वायरल हो रहा है। इसमें इन्फ्लुएंसर मेट्रो के रुकते ही सक्शन कप या टेप से अपना फोन शीशे पर चिपका देते हैं। ट्रेन के चलते ही फोन प्लेटफॉर्म और सुरंग का सिनेमाई शॉट रिकॉर्ड करता है, जबकि क्रिएटर प्लेटफॉर्म पर दौड़ते या डांस करते हुए रील शूट करता है।

येलो लाइन के स्टेशनों पर ऐसे मामले ज्यादा सामने आए हैं। डीएमआरसी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर कहा कि यह हरकत रील बनाने वाले और अन्य यात्रियों दोनों के लिए खतरनाक है। चलती ट्रेन के झटके से फोन गिरने पर ट्रैक के पास खड़े यात्री को चोट लग सकती है या मेट्रो के उपकरणों को नुकसान हो सकता है।

गाजियाबाद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनी महिला वालंटियर फोर्स, 24 थानों से 591 महिलाएं जुड़ीं

गाजियाबाद। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने सामुदायिक भागीदारी की दिशा में एक प्रयास किया है। पुलिस की ओर से महिला वालंटियर फोर्स (एमवीएफ) का गठन किया गया है। इसके लिए कमिश्नरेट के 24 थाना क्षेत्रों से कुल 591 महिलाओं को चिह्नित किया गया है। यह महिलाएं पुलिस और समाज के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुए महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से पुलिस तक पहुंचाने में सहयोग करेंगी।

एमवीएफ में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय और अनुभवी महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इनमें डाक्टर, अधिवक्ता, शिक्षिकाएं, समाजसेवी, गृहिणियां, काउंसलर, उद्यमी और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं शामिल की जा रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य केवल शिकायतों को पुलिस तक पहुंचाना नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना है। महिला वालंटियर्स महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित समस्याओं को पुलिस तक पहुंचाने में मदद करेंगी। साथ ही महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने, जरूरतमंद महिलाओं को सरकारी योजनाओं और सहायता तंत्र की जानकारी देने तथा आवश्यकता पड़ने पर काउंसलिंग और सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने में सहायता करेंगी। स्कूल-कालेज और अन्य संस्थानों में महिला सुरक्षा व साइबर सुरक्षा से जुड़े जागरूकता कार्यक्रमों में भी इनकी भूमिका होगी।

पुलिस ने थाना स्तर पर इस नेटवर्क को स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप सक्रिय करने की योजना बनाई है। वालंटियर्स महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों को पुलिस के संज्ञान में लाने के साथ सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों में भी भाग लेंगी।

दलितों पर अत्याचार, विपक्ष पर एफआईआर अब नहीं चलेगाः संजय दत्त

गुरुग्राम। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बादशाहपुर द्वारा रविवार को वाटिका चौक स्थित औरम कन्वेंशन सेंटर में विशाल ब्लॉक कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी गुरुग्राम (ग्रामीण) के अध्यक्ष वर्धन यादव ने बताया कि वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। सम्मेलन में पहुंचे शीर्ष नेताओं का बादशाहपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक उल्लावास, जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि हरियाणा कभी विकास, कृषि, खेल और वीरता के लिए देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता था, लेकिन भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ी घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। संजय दत्त ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने की मांग की। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार के कुशासन के कारण हरियाणा विकास के कई मानकों पर पिछड़ा है। प्रदेश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है और कानून-व्यवस्था को लेकर आम जनता में चिंता बढ़ी है। उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की व्यवस्था की आलोचना करते हुए संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, समान काम के लिए समान वेतन देने और भविष्य में नियमित भर्तियों को प्राथमिकता देने की मांग की। कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य एवं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विशेष रूप से गुरुग्राम और बादशाहपुर क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश-दुनिया में मिलेनियम सिटी और कॉरपोरेट हब के रूप में पहचान रखने वाला गुरुग्राम आज जलभराव, ट्रैफिक जाम, टूटी सडक़ों और बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था से जूझ रहा है।

टोल पर तैनात कर्मचारी अचानक मुंह के बल गिरा, हुई मौत

फरीदाबाद,एजेंसी। फरीदाबाद में गुरुग्राम रोड स्थित बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर तैनात एक कर्मचारी अचानक खड़े-खड़े मुंह के बल गिरकर मर गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो जिसमें एक कर्मचारी अचानक बैरियर के पास मुंह के बल जा गिरा। वह करीब 25 सेकेंड तक जमीन पर पड़ा तड़पता रहा। इसके बाद वह अचेत हो गया। तभी दूसरा कर्मचारी दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे संभाला। कुछ ही देर में दूसरे कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यह घटना एक सितंबर की बताई जा रही है। जिसके बारे में अब जानकारी सामने आई है।

परिजनों का आरोप है कि कार चालक ने मृतक राजेंद्र को टक्कर मारी, जिसके बाद उसके सिर पर चोट लगी और दस मिनट बाद उसकी मौत हो गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। दरअसल मृतक के परिजनों का आरोप है कि राजेंद्र टोल की इमरजेंसी लाइन पर तैनात था। वहां एक वैगनआर कार ने पीछे हटते समय उसे टक्कर मार दी। इससे उसका सिर सडक़ से जा टकराया। आरोप है कि कार चालक ने राजेंद्र के एक सहयोगी को इलाज के नाम पर एक हजार

रुपए दिए और मौके से फरार हो गया। इसके करीब 10 मिनट बाद राजेंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजनों का आरोप है कि टोल प्रबंधन ने एंबुलेंस से राजेंद्र को अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, ग्वाल पहाड़ी पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, टोल पर कार से टक्कर मारने का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए इत्तेफाकिया कार्रवाई करते हुए शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। मूल रूप से यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला राजेंद्र (36) पिछले करीब 13 साल से फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर बने बंधवाड़ी टोल पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। वह गांव बंधवाड़ी में अपनी बहन के घर पर ही रहता था। उसके तीन बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी 10 साल की बेटी, 8 साल का बेटा और सबसे छोटा 5 साल का बेटा है। करीब 5 साल पहले उसका पत्नी से तलाक हो चुका था। वह अकेले ही बच्चों का पालन-पोषण कर रहा था। गुरुग्राम पुलिस की ग्वाल पहाड़ी चौकी के इंचार्ज नरबीर के मुताबिक, पुलिस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया।

उत्तर प्रदेश 2027: चुनावी बिसात और बदलते

अशोक भाटिया

उत्तर प्रदेश की राजनीति को भारतीय लोकतंत्र का हृदयस्थल माना जाता है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ के गलियारों से होकर गुजरता है, यही कारण है कि देश के इस सबसे बड़े सूबे में होने वाली हर छोटी-बड़ी राजनीतिक हलचल का असर राष्ट्रीय फलक पर साफ दिखाई देता है। वर्ष 2026 की समाप्ति के करीब आते ही और 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के साथ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच शह-मात का खेल पूरी तरह से शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने सूबे की राजनीतिक जमीन को जो नई शक्ल दी थी, उसके बाद हर दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होकर इतिहास रचने की कवायद में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के सहारे दस साल के सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। इस बार का चुनाव केवल पारंपरिक नारों या वादों पर आधारित नहीं रहने वाला, बल्कि यह जमीन पर रची जा रही नई सामाजिक और गठबंधन राजनीति की प्रयोगशाला बनने जा रहा है।

इस राजनीतिक उठापटक और नए समीकरणों के निर्माण के बीच हाल ही में लखनऊ से एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक खबर सामने आई, जिसने राज्य के सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के बीच लखनऊ में लगभग 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे तक चली बंद कमरे की मैराथन मुलाकात ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। इस मुलाकात के मायने केवल एक शिष्टाचार भेंट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह 2027 के महासमर से पहले उत्तर प्रदेश की युवा और छात्र राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। आशुतोष रांका और अखिलेश यादव के बीच हुई इस चर्चा के केंद्र में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के मुद्दे, लगातार होती परीक्षाओं के पेपर लीक, बेरोजगारी, छात्रों की समस्याएं और उच्च शिक्षा में आ रही गिरावट जैसे विषय शामिल रहे। पार्टी के भीतर और बाहर इस मुलाकात को 'प्लान 2027' के एक अहम हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया और बेहद जागरूक मतदाता वर्ग तैयार हो चुका है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक 'जेन-जी' या पहली बार मतदान करने वाले युवा कहते हैं। यह युवा वर्ग पारंपरिक जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर रोजगार, निष्पक्ष परीक्षाओं और आधुनिक अवसरों की मांग कर रहा है। अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं कि केवल पारंपरिक मुस्लिम-यादव समीकरण या केवल सामान्य गठबंधनों के बूते भाजपा जैसी विशाल और साधन-संपन्न चुनावी मशीनरी को मात देना असंभव है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद सपा अब छोटे-छोटे वैचारिक समूहों, छात्र संगठनों और युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरों को अपने पाले में लाकर भाजपा के उस युवा वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है, जो कभी भगवा दल की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। रांका और अखिलेश यादव की यह मुलाकात इस बात की तस्दीक करती है कि विपक्ष इस बार युवाओं के आक्रोश को एक ठोस राजनीतिक वोट बैंक में बदलने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है।

हालांकि, इस मुलाकात पर भाजपा ने भी फौरन तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है कि विपक्ष के पास कोई ठोस नीति या विकास का एजेंडा नहीं है, इसलिए वह केवल भ्रम फैलाने और छोटे-छोटे संगठनों के सहारे अपनी डूबती नैया बचाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन राजनीति के जानकार इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके मूल में युवाओं और छात्रों का आंदोलन या उनका असंतोष ही रहा है। ऐसे में सीजेपी जैसी युवा केंद्रित ताकतों और सपा का करीब आना भविष्य के एक नए और बड़े सामाजिक-राजनैतिक मोर्चे की बुनियाद रख सकता है। यदि हम उत्तर प्रदेश की समूची राजनैतिक बिसात पर नजर डालें, तो इस समय सबसे बड़ा टकराव नैरेटिव यानी विमर्श गढ़ने को लेकर चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस बार 'आरक्षण' और 'संविधान' को अपनी राजनीति के केंद्र में रख दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को 'संविधान बचाओ' के नारे से जो अप्रत्याशित लाभ मिला था, अखिलेश यादव उसे 2027 तक कायम रखना चाहते हैं। हालिया महीनों में उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की स्थिति, 69000 शिक्षक भर्ती का विवाद और पिछड़े-दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व को लेकर सपा ने एक आक्रामक रुख अख्तियार किया है। अखिलेश यादव लगातार जनसभाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से यह

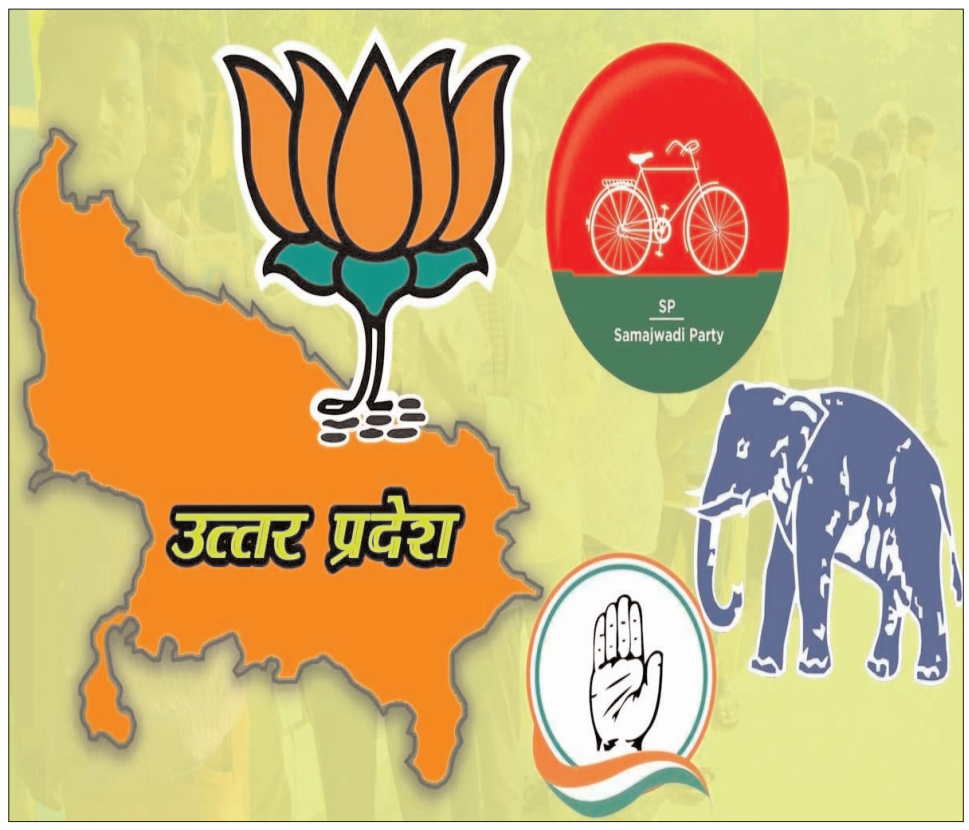

संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान सत्ताधारी दल दलितों और पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। इस नैरेटिव के जरिए सपा सीधे तौर पर भाजपा के गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित वोट बैंक पर निशाना साध रही है, जिसने पिछले एक दशक से भाजपा की जीत में रीढ़ की हड्डी का काम किया है। सपा की इस रणनीति के जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी खामोश नहीं बैठी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने अपनी संगठन मशीनरी को पूरी तरह से चुनावी मोड में डाल दिया है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर का ढांचा माना जाता है। पार्टी ने इस बार कागजी दावों को खारिज करते हुए हर एक बूथ कमेटी का भौतिक सत्यापन शुरू किया है। खासकर उन बूथों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जहां पिछले चुनाव में विपक्ष को बढ़त मिली थी। इसके साथ ही, भाजपा सरकार अपनी कानून-व्यवस्था की सख्त छवि, बुनियादी ढांचे का विकास (जैसे एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारे) और केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के एक बड़े नेटवर्क के भरोसे मैदान में उतर रही है।

भाजपा का मानना है कि विकास और सुशासन का उनका यह 'डबल इंजन' मॉडल विपक्ष के जातिगत ध्रुवीकरण के प्रयासों को विफल कर देगा। लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन के भीतर की आंतरिक खींचतान भी पूरी तरह सतह पर आ चुकी है। गठबंधन में शामिल छोटे दल जैसे निषाद पार्टी के डॉ. संजय निषाद, अपना दल (सोनेलाल) की अनुप्रिया पटेल और सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और सीटों के सम्मानजनक बंटवारे के लिए भाजपा पर लगातार दबाव बना रहे हैं। हाल ही में एक सार्वजनिक मंच पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के भावुक होने और आंसुओं के छलकने की घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भारी उबाल ला दिया था। जहां संजय निषाद ने इसे अपने समाज को हक न मिल पाने की पीड़ा बताया, वहीं अखिलेश यादव ने तुरंत इस पर तंज कसते हुए इसे भाजपा के साथ जाने का 'पश्चाताप और प्रायश्चित' करार दे दिया। यह घटना दर्शाती है कि निषाद और अन्य अति-पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को लेकर दोनों पक्षों में कितनी जबर्दस्त रस्साकशी चल रही है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि निषाद समाज भी उनके 'पीडीए' का एक अभिन्न हिस्सा है और यदि उनकी सरकार आती है, तो वे जातीय जनगणना कराकर हर समाज को उसका वास्तविक हक देंगे। दूसरी तरफ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का 'इंडिया' गठबंधन भी एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। यद्यपि अखिलेश यादव और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने बार-बार यह दोहराया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर सीटों के बंटवारे और प्रादेशिक नेतृत्व को लेकर दोनों दलों के स्थानीय नेताओं के बीच महत्वाकांक्षाओं का टकराव साफ दिखाई देता है। कांग्रेस जहां लोकसभा चुनाव के उत्साह के बाद उत्तर प्रदेश में अपने पुराने गौरव को हासिल करने के लिए अधिक सीटों की मांग कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखते हुए कांग्रेस को सीमित सीटों पर समेटने की रणनीति बना रही है। इसके अतिरिक्त, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती की खामोशी और उनकी अंदरूनी बैठकें भी इस त्रिकोणीय मुकाबले को और दिलचस्प बना रही हैं। मायावती अपने खिसकते दलित वोट बैंक को सहेजने के लिए नए सिरे से कैडर कैंप आयोजित कर रही हैं। यदि बसपा अपने पारंपरिक वोट को बचाने में सफल रहती है, तो इसका सीधा नुकसान सपा-कांग्रेस गठबंधन को उठाना पड़ सकता है, जिससे अंतत: भाजपा को लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। सियासत के इस खेल में शह और मात के मोहरे बिछ चुके हैं। जनता शांत है, लेकिन वह हर दल की चालों को बहुत बारीकी से देख रही है। रोजगार की तलाश में भटकता युवा, महंगाई से जूझता आम नागरिक और अपने अधिकारों के प्रति सजग होता जातियों का समूह ही अंतत: यह तय करेगा कि 2027 में लखनऊ के सिंहासन पर किसका राजतिलक होगा। फिलहाल, राजनैतिक दलों की यह सरगर्मी और रणनीतिक मुलाकातों का दौर यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश का आगामी चुनावी संग्राम बेहद रोमांचक, अप्रत्याशित और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।

पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं की गति इस बदलाव को स्पष्ट रूप से दिखाती है। अलग-अलग देशों के साथ बैठकें केवल पारंपरिक कूटनीतिक मुलाकातें नहीं रह गई हैं बल्कि उनमें व्यापार, निवेश, रक्षा तकनीक, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा और रोजगार जैसे ठोस मुद्दों पर समझौते किए जा रहे हैं। इस रणनीति के पीछे सबसे बड़ा कारण वैश्विक अनिश्चितता है। अमेरिका की व्यापार नीति में बदलाव, भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ और रूसी तेल खरीदने को लेकर पैदा हुआ विवाद नई दिल्ली के लिए एक चेतावनी की तरह सामने आया। जिस अमेरिका को भारत लंबे समय से एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता रहा है, उसी के साथ व्यापारिक तनाव ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या भारत को अपनी आर्थिक निर्भरता को और अधिक विविध बनाना चाहिए? उत्तर काफी हद तक 'हां' में दिखाई देता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एकल निर्यात बाजार रहा है। ऐसे में अमेरिकी बाजार में किसी भी बड़े व्यापारिक व्यवधान का भारतीय उद्योग, निर्यातकों और रोजगार पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यूरोप, ब्रिटेन, एशिया और अन्य क्षेत्रों में नए बाजार तलाशना भारत के लिए केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं बल्कि आर्थिक आवश्यकता भी बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया विदेश नीति को एक तरह की डील-मेकिंग डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। विदेश यात्राओं में अब केवल साझा बयान या राजनीतिक दोस्ती महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि ठोस लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत केवल विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि तकनीक, उत्पादन क्षमता और वैश्विक बाजार तक पहुंच भी चाहता है। जर्मनी से पनडुब्बी तकनीक, फ्रांस के साथ एआई और गवर्नेंस, दक्षिण कोरिया के साथ जहाज निर्माण और निवेश तथा यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते जैसे प्रयास इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। लगभग

बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की नई विदेश नीति

अमरेश द्विवेदी

आज की वैश्विक राजनीति में किसी एक बड़े देश के साथ मजबूत संबंध होना पर्याप्त नहीं रह गया है। व्यापार युद्ध, टैरिफ, रूस-यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, चीन की बढ़ती ताकत और ऊर्जा आपूर्ति की अनिश्चितता ने दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अपनी विदेश नीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत भी इस बदलाव से अछूता नहीं है। गत दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तुलना करते हुए एक लेख छापा है। जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जब-जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनका किस तरह से सम्मान होता है और उस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो नोबेल पुरस्कार पाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में पिछले कुछ समय में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है। भारत अब केवल अमेरिका या किसी एक बड़े शक्ति-केंद्र पर निर्भर रहने के बजाय यूरोप, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे और अन्य देशों के साथ समानांतर रूप से आर्थिक एवं रणनीतिक संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं की गति इस बदलाव को स्पष्ट रूप से दिखाती है। अलग-अलग देशों के साथ बैठकें केवल पारंपरिक कूटनीतिक मुलाकातें नहीं रह गई हैं बल्कि उनमें व्यापार, निवेश, रक्षा तकनीक, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा और रोजगार जैसे ठोस मुद्दों पर समझौते किए जा रहे हैं। इस रणनीति के पीछे सबसे बड़ा कारण वैश्विक अनिश्चितता है। अमेरिका की व्यापार नीति में बदलाव, भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ और रूसी तेल खरीदने को लेकर पैदा हुआ विवाद नई दिल्ली के लिए एक चेतावनी की तरह सामने आया। जिस अमेरिका को भारत लंबे समय से एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता रहा है, उसी के साथ व्यापारिक तनाव ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या भारत को अपनी आर्थिक निर्भरता को और अधिक विविध बनाना चाहिए? उत्तर काफी हद तक 'हां' में दिखाई देता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एकल निर्यात बाजार रहा है। ऐसे में अमेरिकी बाजार में किसी भी बड़े व्यापारिक व्यवधान का भारतीय उद्योग, निर्यातकों और रोजगार पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यूरोप, ब्रिटेन, एशिया और अन्य क्षेत्रों में नए बाजार तलाशना भारत के लिए केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं बल्कि आर्थिक आवश्यकता भी बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया विदेश नीति को एक तरह की डील-मेकिंग डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। विदेश यात्राओं में अब केवल साझा बयान या राजनीतिक दोस्ती महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि ठोस लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत केवल विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि तकनीक, उत्पादन क्षमता और वैश्विक बाजार तक पहुंच भी चाहता है। जर्मनी से पनडुब्बी तकनीक, फ्रांस के साथ एआई और गवर्नेंस, दक्षिण कोरिया के साथ जहाज निर्माण और निवेश तथा यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते जैसे प्रयास इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। लगभग दो दशकों से चल रही व्यापार वार्ता बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच आगे बढ़ी। भारत ने यूरोपीय उत्पादों के लिए कुछ टैरिफ कम करने पर सहमति जताई, जबकि बदले में भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच की संभावना बनी। यूरोप भारत के लिए सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है। वह तकनीक, पूंजी, उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण, हरित तकनीक और रक्षा सहयोग का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। फ्रांस के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी इसका उदाहरण है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध पहले से मजबूत हैं लेकिन अब एआई, डिजिटल तकनीक और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ रही है। भारत के लिए यूरोप के साथ संबंधों का महत्व इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इससे अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कुछ हद तक कम की जा सकती है। यूरोप के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार खोल सकते हैं। इससे ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और आईटी जैसे क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है। इसके अलावा यूरोपीय कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो इससे पूंजी और तकनीक के साथ रोजगार भी बढ़ सकता है। लेकिन मुक्त व्यापार समझौते का दूसरा पहलू भी है। विदेशी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार अधिक खुलने से घरेलू कंपनियों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ेगा। विशेष रूप से छोटी और मध्यम भारतीय कंपनियां यदि उत्पादकता और तकनीक में पीछे हैं तो उनके लिए यूरोपीय कंपनियों से मुकाबला करना कठिन हो सकता है। इसलिए केवल बाजार खोलना पर्याप्त नहीं है। भारत को अपने घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ानी होगी। भारत की नई रणनीति को अमेरिका से दूरी बनाने के रूप में देखना सही नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि भारत और अमेरिका के संबंध रक्षा, तकनीक, शिक्षा, निवेश और इंडो-पैसिफिक रणनीति के कारण बेहद महत्वपूर्ण हैं। दोनों देश चीन की बढ़ती ताकत को लेकर भी कई समान चिंताएं रखते हैं। लेकिन व्यापार और रूस के मुद्दे पर मतभेदों ने भारत को यह एहसास कराया है कि किसी भी एक साझेदार पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम पैदा कर सकती है। यही कारण है कि भारत एक ओर अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है तो दूसरी ओर जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अन्य देशों के साथ अपने विकल्प मजबूत कर रहा है। यह रणनीति 'बैलेंसिंग' से अधिक 'विविधता' की रणनीति दिखाई देती है। भारत का संदेश साफ है कि किसी एक देश के साथ संबंध खराब होने की स्थिति में भी उसकी अर्थव्यवस्था और रणनीतिक हित पूरी तरह प्रभावित न हों।

रूस के साथ संबंध: पुरानी दोस्ती की नई परीक्षा रूस भारत की विदेश नीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के दशकों पुराने संबंध हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी रूस भारत के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के सामने कठिन कूटनीतिक संतुलन पैदा हुआ। पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करते हुए भारत रूस से भी रक्षा और ऊर्जा संबंध बनाए रखना चाहता है। शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर रूस के साथ संवाद जारी रखना इसी रणनीति का हिस्सा है। रूस के साथ संबंध भारत को ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराते हैं। इससे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता बढ़ती है। लेकिन रूस पर अत्यधिक निर्भरता भी जोखिम पैदा कर सकती है। युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस की अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक व्यापारिक भूमिका बदल रही है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी रक्षा आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा किसी एक स्रोत पर निर्भर न हो। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के बड़े हिस्से के लिए कच्चे तेल का आयात करता है। इसलिए पश्चिम एशिया में किसी भी बड़े संकट का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य इसका सटीक उदाहरण है। यदि इस मार्ग में लंबे समय तक व्यवधान पैदा होता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और भारत के आयात पर दबाव पड़ सकता है। इसका असर केवल पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं होगा। महंगा तेल परिवहन लागत बढ़ाएगा, जिससे खाद्य पदार्थों और औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं। इसीलिए भारत को ऊर्जा स्रोतों और परिवहन मार्गों दोनों में विविधता लानी होगी। सऊदी अरब, यूएई, रूस, अमेरिका और अन्य उत्पादकों के साथ संबंध बनाए रखना तथा वैकल्पिक ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढांचे पर निवेश करना लंबे समय में भारत के लिए जरूरी है। भारत की अगली बड़ी चुनौती मैन्युफैक्चरिंग है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी तकनीकों के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और अन्य महत्वपूर्ण खनिज जरूरी हैं। यदि भारत इन खनिजों के लिए सीमित देशों पर निर्भर रहता है तो भविष्य में सप्लाई चेन संकट उसकी औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को प्रभावित कर सकता है। इसलिए भारत का अलग-अलग देशों के साथ खनिज और औद्योगिक साझेदारी विकसित करना आर्थिक सुरक्षा का हिस्सा है। यहां विदेश नीति सीधे 'मेक इन इंडिया' और रोजगार से जुड़ जाती है। यदि विदेशी तकनीक भारत में आती है, लेकिन उत्पादन विदेश में ही होता रहता है, तो भारत को सीमित लाभ मिलेगा। असली फायदा तब होगा जब तकनीक के साथ भारत में उत्पादन, अनुसंधान और रोजगार भी पैदा हों। भारत की इस बहु-दिशात्मक विदेश नीति के कई स्पष्ट फायदे हैं। पहला फायदा जोखिम में कमी। यदि एक बाजार में समस्या आती है तो दूसरे बाजार भारतीय निर्यात को सहारा दे सकते हैं। दूसरा तकनीक का हस्तांतरण। रक्षा, एआई, जहाज निर्माण और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विदेशी तकनीक भारत की औद्योगिक क्षमता बढ़ा सकती है। तीसरा निवेश, अलग-अलग देशों के साथ आर्थिक समझौते विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। चौथा—रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग और नए औद्योगिक कॉरिडोर रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। पांचवां रणनीतिक स्वायत्तता, भारत किसी एक शक्ति के दबाव में आने से बच सकता है।

विचार

शिक्षा जगत में सत्यनिष्ठा की भावना जागृत हो

गिरीश्वर मिश्र

पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में जाहिर हुई गंभीर अनियमितताओं के चलते पहले दिल्ली, फिर रांची और पटना में नई पीढ़ी ने जिस तरह विरोध और असंतोष जताया वह अभूतपूर्व था। इन सब घटनाओं ने शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भरोसे और सत्यनिष्ठा (इंटीग्रिटी) को प्रश्नांकित किया है। शिक्षा से जुड़े सभी लोगों के मन में अब कई प्रश्न उठ रहे हैं। नीट पेपर लीक के मामले में अध्यापकों की संदिग्ध भूमिका के लिए गिरफ्तारी और एनटीए के छह सौ विषय-विशेषज्ञों और पचास से अधिक अधिकारियों की बर्खास्तगी पूरी व्यवस्था की साख को धूमिल कर रही है। इन सबके बीच संलग्न व्यक्तियों की सत्यनिष्ठा संदेह के घेरे में आ गई है। वस्तुत: शिक्षा संस्थानों के संचालन में सत्यनिष्ठा एक धुरी का काम करती है। यही सोचकर सत्यमेव जयते नानृतम् को याद किया जाता है। सत्य की विजय और असत्य की पराजय की बात जीवन की व्यवस्था को संभव बनाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही सत्य महत्वपूर्ण मानते हुए घोषित किया गया कि सत्य पर ही धरती टिकी हुई है: सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्य में स्थित होकर, धर्म के अनुकूल कर्म और लोक-संग्रह में योगदान का लक्ष्य सबके लिए निर्धारित किया गया। शिक्षा और विद्या के क्षेत्र में मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि प्रतिष्ठित किया गया। तैत्तिरीय उपनिषद में स्नातक के लिए 'सत्यम् वद', 'धर्मम् चर', 'स्वाध्यायान्मा प्रमद' आदि निर्देशों का विधान, पुरुषार्थ की व्यवस्था में 'अर्थ' और 'काम' को धर्म के अनुरूप साधने की बात कही गई। इसी तरह मन, वचन और कर्म में एका बनाए रखने को एक महात्मा का लक्षण माना गया है। बाह्य और आभ्यंतर जगत दोनों में तालमेल को वांछित ठहराया गया। इन सबका एक ही आशय था कि पारस्परिक संगति और भरोसा बना रहे। ज्ञान के अर्जन, उसके संचार और सुरक्षित रूप में अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का भार गुरु को दिया गया जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है । ज्ञान-दान की प्रक्रिया में गुरु द्वारा अध्ययन, प्रवचन और प्रयोग सभी आता था। जैसा कि महाकवि कालिदास ने व्यक्त किया है- कुछ गुरु स्वयं तो पूरे दक्ष होते हैं पर दूसरों को नहीं समझा पाते, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों तक ज्ञान पहुँचा तो देते हैं पर खुद उतने दक्ष नहीं होते, पर श्रेष्ठ गुरु स्वयं भी दक्ष होता है और दूसरों को भी भली-भाँति सिखा देता है। अर्थात् शिक्षण का कार्य सूचना का संकलन ही नहीं उसे लोगों में बांटने और जीवन में उतारने से भी जुड़ा हुआ है।

इसी को ध्यान में रखकर गुरु की संस्था को परब्रह्म कह कर प्रतिष्ठित किया गया: गुरु: साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम:। समाज ने गुरु से अनेक अपेक्षाएं सुनिश्चित कर दीं। मानव शिशु में में विचार और चिंतन की शक्ति देना गुरु का एकल दायित्व बना। वह शिष्यों के भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिश्रुत था। एक आदर्श व्यक्ति के रूप में गुरु अपने आचरण को हर तरह से निष्कलुष रखने के लिए तत्पर रहता था। गुरु के भरण-पोषण के साथ विद्यादान के लिए गुरुकुल बने जिनको संचालित करना समाज का दायित्व था पर गुरुकुल में समाज या राजा की कोई दखलंदाज़ी नहीं थी। भारत में की गुरुओं की परंपरा बड़ी लंबी है जिसमें वशिष्ठ, विश्वामित्र, चाणक्य, समर्थ गुरु रामदास और परमहंस रामकृष्ण जैसे महान और प्रतापी गुरु हुए जिन्होंने अपने शिष्यों से राष्ट्र को सबल नेतृत्व दिया और मानदंड स्थापित किया। वस्तुत: गुरु और शिष्य एक-दूसरे के पूरक रहे। गुरु होने के लिए निष्ठा के साथ दीर्घकाल की नि:स्वार्थ साधना की जरूरत होती थी इसलिए गुरु होना सरल न था। यह अन्य व्यवसायों से इस अर्थ में भिन्न था कि इसमें गुरु को स्वायत्तता प्राप्त थी और वह भौतिक आवश्यकताओं की और निश्चिंत रहता था। वह अपने आचरण से समाज में नैतिक मानक स्थापित करता था और समाज भी अपने को गुरु का उपकृत मानता था। तभी 'गुरुर्देवो भव' का निर्देश प्रचलित हुआ और गुरु ऋण सबका दायित्व बना। कालक्रम में अनेक परिवर्तन आते रहे और आज हम शिक्षा और शिक्षक दोनों की स्थिति में बड़ा बदलाव पा रहे हैं। आज जहाँ एक तरफ़ अमृतकाल में सर्वांगीण उन्नति के लिए देश कटिबद्ध हो रहा है तो दूसरी शैक्षिक सत्यनिष्ठा में गिरावट चिंता का विषय बन रहा है। अध्यापन स्तर में गिरावट, साहित्य-चोरी में वृद्धि, परीक्षा से जुड़ी अनियमितताएं और शोध कार्य में मौलिकता और समालोचक बुद्धि की जगह दुहराव की वृद्धि अकादमिक व्यवस्था में आ रहे संकट की ओर संकेत करते हैं। यह दुरावस्था अनेक कारणों से हो रही है जो मिलकर ऐसी अकादमिक पारिस्थितिकी बना रहे हैं जो गुणवतापूर्ण शिक्षा के मार्ग में लगातार रोड़े अटका रही है। विशेष रूप से शैक्षिक संस्थाओं वर्षों से अध्यापकों की संख्या में लगातार कमी, संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं और संसाधनों का अभाव तथा अनर्गल राजनैतिक हस्तक्षेप के चलते अकादमिक जगत की गरिमा घट रही है।

एक नजर

डुमरिया दियारा से युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका

कटिहार,एजेंसी। कुरसेला थाना क्षेत्र की मुरादपुर पंचायत के वार्ड संख्या छह स्थित डुमरिया दियारा में रविवार को 25 वर्षीय मोहम्मद तबारक का शव बरामद किया गया। शव बांसबिट्टा के पास बने एक मचान के समीप मिला। प्रथम दृष्टया धारदार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर कुरसेला थानाध्यक्ष राकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। मृतक के चचेरे भाई मोहम्मद जिबराइल ने प्रेम प्रसंग के विवाद को लेकर तबारक की हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है। हालांकि, घटना के कारणों और इसमें संलिप्त लोगों के बारे में पुलिस की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। मामले में सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम ने किया सघन निरीक्षण, राहत कार्य अविलंब शुरू करने के दिए निर्देश

कटिहार, 06 सितंबर (हि.स.)। जिले में विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि और बाढ़ से उत्पन्न विषम परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने रविवार को वरीय प्रशासनिक

पदाधिकारियों की टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप प्रभावित परिवारों के लिए सभी तरह के राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर शुरू करने का कड़ा निर्देश दिया। सघन दौरे के क्रम में जिलाधिकारी कुरसेला प्रखंड अंतर्गत तीनघरिया पंचायत के मालगोदाम पहुंचे। वहां उन्होंने जलजमाव और बाढ़ से घिरे लोगों की समस्याएं सुनीं तथा विस्थापित व जरूरतमंद परिवारों के बीच पॉलीथिन शीट का वितरण कराया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी पीड़ित परिवार को खुले आसमान के नीचे न रहना पड़े, इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त संख्या में पॉलीथिन शीट और सुरक्षित आश्रय स्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार कैंप करें। जलस्तर की पल-पल की निगरानी, तटबंधों की सुरक्षा, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, आवश्यक जीवनरक्षक दवाएं तथा पशु चारे की व्यवस्था में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आवश्यकतानुसार कम्युनिटी किचन और नावों का परिचालन भी तत्काल प्रभाव से शुरू कराया जाए। इस दौरान बरारी विधायक विजय सिंह भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया। निरीक्षण दल में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) नेहा कुमारी, अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) सूरज कुमार, अपर समाहर्ता (एडीएम), एडीएम (आपदा प्रबंधन) सहित संबंधित तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता, स्थानीय बीडीओ एवं सीओ उपस्थित थे।

राघोपुर का दर्द दिख रहा है, बाकी भागलपुर क्यों नहीं? मंत्रियों के घरों के कारण भेदभाव का आरोपः गौतम कुमार

भागलपुर। बिहार जनसंघर्ष समिति के संयोजक गौतम कुमार ने भागलपुर जिले में गंगा के भीषण कटाव और बाढ़ की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार, प्रशासन और मीडिया पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि खरीक प्रखंड के राघोपुर में कटाव की स्थिति बेहद गंभीर है और समिति राघोपुर के लोगों के साथ खड़ी है, लेकिन बाढ़ और कटाव का दर्द सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। जिले के नाथनगर, सबौर, सुल्तानगंज और इस्माइलपुर सहित कई अन्य प्रखंडों में भी हजारों लोग इस आपदा से पूरी तरह अस्त-व्यस्त हैं, मगर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। गौतम कुमार ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि आज सरकार, प्रशासन और मीडिया का पूरा ध्यान केवल राघोपुर पर केंद्रित दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां बिहार के दो कैबिनेट मंत्रियों के घर प्रभावित हैं, जिनमें से एक मंत्री का घर पानी में डूबा हुआ है। उन्होंने पूछा कि क्या बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा का महत्व अब इस बात से तय होगा कि आपदा की जद में किसका घर आया है? बाढ़ किसी मंत्री का घर देखकर नहीं आती, इसलिए राहत कार्य भी मंत्रियों के घरों को देखकर नहीं चलाए जाने चाहिए। प्रशासनिक कार्यों और इंजीनियरिंग के तरीकों पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ की इस विकराल स्थिति और गंगा की तेज धारा के बीच बोरी में मिट्टी और बालू भरकर बहाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या विशेषज्ञ और इंजीनियर यह नहीं जानते कि तेज बहाव के बीच ऐसी अस्थायी कोशिशें कितनी अप्रभावी साबित होती हैं? अगर यह प्रयास टिकाऊ नहीं है, तो जनता के खून-पसीने की कमाई को पानी में क्यों बहाया जा रहा है? बिहार जनसंघर्ष समिति के संयोजक ने मांग की है कि कटाव रोकने के नाम पर दिखावटी कार्यों में खर्च होने वाले पैसे का बेहतर उपयोग बाढ़ पीड़ितों की सीधी मदद के लिए होना चाहिए। इस राशि से पीड़ितों के लिए तत्काल राहत सामग्री, सुरक्षित पुनर्वास, भोजन, दवाइयां, नावों की पर्याप्त व्यवस्था, शुद्ध पेयजल और उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने बिहार सरकार और जिला प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि भागलपुर के सभी बाढ़ एवं कटाव प्रभावित क्षेत्रों का बिना किसी भेदभाव के जमीनी आकलन किया जाए और सभी पीड़ितों के लिए समान रूप से तत्काल राहत, बचाव और पुनर्वास की व्यापक व्यवस्था लागू की जाए।

बिहार के आरा में गाड़ी संख्या 15483 महानंदा एक्सप्रेस डिरेल, स्टेशन मास्टर संस्पेंड

पटना,एजेंसी। बिहार में भोजपुर जिले के आरा रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब 4 बजे 15483 अलीपुरद्वार जंक्शन-दिल्ली महानंदा एक्सप्रेस डिरेल हो गई। हादसे में रेलगाड़ी की एक एसी और एक जनरल बागी पटरी से उतर गई। मामले में आरा स्टेशन मास्टर एनके राय को सस्पेंड कर दिया गया है। महानंदा एक्सप्रेस के डिरेल होने के कारण दिल्ली-हावड़ा रूट प्रभावित हुआ। वंदे भारत, विभूति एक्सप्रेस, गांधी धाम, कैप्टल एक्सप्रेस, इंटरसिटी, गरीब रथ, पैसेंजर, उधना एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें लेट हैं। यह ट्रेन आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-2 पर खड़ी थी। अपने निर्धारित समय के अनुसार सुबह 4:12 बजे ट्रेन दिल्ली की ओर रवाना होने के लिए प्लेटफार्म से खुली थी।

ट्रेन खुलने के बाद अचानक बक्सर की बजाय सासाराम की तरफ निकलने लगी। परिचालन के दौरान सिग्नल में अचानक तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी, जिसके कारण ट्रेन दिल्ली की जगह सासाराम लाइन की ओर चली गई। ट्रेन स्टेशन से कुछ दूरी आगे पश्चिमी ओवरब्रिज के समीप पहुंची थी। तभी प्लेटफार्म से केवल 200 मीटर आगे जाते ही अप लाइन में ट्रेन अचानक बेपटरी हो गई। घटना के बाद सस्पेंड होने वाले स्टेशन प्रबंधक एनके राय ने बताया कि सुबह 4 बजकर 20 मिनट पर मुझे ट्रेन के डिरेल होने की सूचना मिली थी। मैं तुरंत घर से गाड़ी रिजर्व कर 10 मिनट पर घटनास्थल पर पहुंच गया। घटनास्थल पर मैंने देखा कि एसएलआर और दूसरी एच-1 बोगी डिरेल हुई है। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर बैठाया स्टेशन मास्टर ने बताया कि दोनों बोगियों के दो-दो पहिए पटरी से उतरे थे। इसके बाद हम लोगों ने अधिकारियों से बात कर जानकारी दी। इसके बाद

अनाउंस करके ट्रेन के यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बैठा दिया गया। इसके बाद प्रोसेस के तहत दूसरे इंजन से ट्रेन के डिरेल बोगी को छोड़ गाड़ी को रिवर्स कर दूसरी तरफ लाया गया। एनके राय ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, जो मेरा कर्तव्य था, मैंने उसे किया। मैं तो स्पॉट पर था और सबसे पहले पहुंचने वाला मैं ही था, लेकिन फिर भी मुझे सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में लापरवाही ड्राइवर की है। महानंदा एक्सप्रेस के लोको पायलट उमाशंकर पांडेय ने बताया, मेन लाइन और मेरी गाड़ी जिस ट्रैक पर खड़ी थी, दोनों का सिग्नल ग्रीन था। मैं ट्रेन को लेकर ग्रीन सिग्नल वाले ट्रैक पर लेकर आगे बढ़ा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का पॉइंट दूसरी ओर बना हुआ है, मैं दूसरी ओर जा रहा हूं, तुरंत मैंने ट्रेन रोक दी। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा कि मेरी गाड़ी गलत जा रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ग्रीन सिग्नल आपकी गाड़ी के लिए नहीं था। इसके बाद मैंने गाड़ी को खड़ा कर दिया। इसके बाद मुझसे कहा गया कि गाड़ी को आप धीरे-धीरे रिवर्स में ले लीजिए। लोको पायलट ने बताया कि जैसे ही मैं गाड़ी को रिवर्स करने लगा, तो कुछ टेक्निकल दिक्कत आई। पूर्व मध्य रेलवे (पूमरे) के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने फोन पर बातचीत में बताया कि घटना में कोई जान-माल की हानि नहीं हुई है। पटरी से उतरी बोगियों के पहियों को जैक की मदद से पटरी पर चढ़ाने का काम किया गया। तीन घंटे की मशक्कत के बाद अप लाइन पर करबी साढ़े सात बजे परिचालन दोबारा शुरू कर दिया गया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने वरिष्ठ जनसंघ कार्यकर्ता जोहन राम के निधन पर शोक व्यक्त किया

पटना,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने वरिष्ठ जनसंघ कार्यकर्ता, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं अरवल जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष जोहन राम के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। 90 वर्षीय जोहन राम अरवल जिले के करपी के रहने वाले थे। उनके निधन की खबर मिलते ही भाजपा प्रदेश कार्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। संजय सरावगी ने कहा कि जोहन राम ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रवादी विचारधारा और संगठन की सेवा में समर्पित कर दिया। जनसंघ के समय से ही संगठन से जुड़े जोहन राम तृतीय वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता थे। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और विचारधारा को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका अनुशासन, निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण कार्यकर्ताओं के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने कहा कि जोहन राम का राजनीतिक और सामाजिक जीवन भी काफी सक्रिय रहा। वर्ष 1972 में उन्होंने जहानाबाद के मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें महज 3,800 मतों से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में पराजय के बावजूद उन्होंने जनसेवा और संगठन के कार्यों से अपना नाता नहीं तोड़ा तथा लगातार सक्रिय रहे। संजय सरावगी ने कहा कि वर्ष 2001 में जोहन राम कांको, जहानाबाद से जिला परिषद सदस्य चुने गए। इसके बाद वर्ष 2006 में अरवल जिले के वंशी से जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने अरवल जिला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि जोहन राम जहानाबाद-अरवल संयुक्त संगठन जिला के महामंत्री तथा बाद में अरवल जिला के जिला महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक दायित्वों का भी निर्वहन कर चुके थे। वर्तमान में वह भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य के रूप में संगठन को अपना मार्गदर्शन दे रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जोहन राम जैसे वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ताओं का जीवन पार्टी की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण का उदाहरण है। उनके निधन से भाजपा ने एक अनुभवी, कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता खो दिया है। संजय सरावगी ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की।

बाढ़ की मार अब आम आदमी की रसोई पर, भागलपुर में सब्जियों के दाम आसमान पर

भागलपुर। जिले में गंगा और कोसी नदियों के उफान के कारण बाढ़ का संकट अब केवल खेतों और ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं रह गया है। बाढ़ का सीधा और तीखा असर अब आम लोगों की थाली और घरेलू बजट पर दिखने लगा है। दियारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ का पानी घुसने से हरी सब्जियों की खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे स्थानीय मंडियों में हरी सब्जियों की आवक न के बराबर रह गई है। सब्जी मंडी के कारोबारियों के मुताबिक, भागलपुर शहर और आसपास के बाजारों में अधिकांश हरी सब्जियां दियारा इलाकों से आती थीं। लेकिन खेतों के जलमग्न होने के कारण लोकल सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। मांग को पूरा करने के लिए अब व्यापारियों को बाहरी जिलों और राज्यों से सब्जियां मंगानी पड़ रही हैं, जिससे परिवहन लागत बढ़ गई है और कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं।

स्थानीय सब्जी मंडियों में लौकी, परवल, भिंडी, खीरा और कद्दू जैसी रोजमर्रा की सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल आया है। बाढ़ से पहले जो सब्जियां सामान्य दामों पर मिल रही थीं, उनकी कीमतें अब दोगुनी या उससे भी अधिक हो गई हैं। इससे मध्यम और गरीब परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह चरमरा गया है। बाजार में खरीदारी करने आए आम उपभोक्ताओं का कहना है कि महंगाई के कारण अब हरी सब्जियां खरीदना जेब पर भारी पड़ रहा है। लोग अब हरी सब्जियों के बजाय आलू-सोयाबीन जैसी चीजों से काम चलाने को मजबूर हैं। मंडियों के थोक और खुदरा विक्रेताओं का स्पष्ट कहना है कि जब तक दियारा क्षेत्र से पानी पूरी तरह नहीं निकल जाता और दोबारा बुवाई शुरू नहीं होती, तब तक आम जनता को महंगी सब्जियों से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है।

भागलपुर की विभिन्न मंडियों (जैसे मंदरोजा, तिलकामांझी और मिरजानहाट) में बाढ़ के बाद सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल आया है। स्थानीय दुकानदारों और आढ़तियों के अनुसार, बाढ़ से पहले और बाढ़ के बाद की कीमतों में दोगुने तक का अंतर आ चुका है। कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण स्थानीय दियारा क्षेत्रों एवं जिच्छो-सरधो, सरधो, धनकर और लोदीपुर में करीब 2000 हेक्टेयर में लगी हरी सब्जियों की फसल पूरी तरह डूब कर बर्बाद हो चुकी है। इस कारण मंडियों में लोकल आवक लगभग शून्य हो गई है।

बिजली गुल होते ही लिफ्ट में फंसीं जीविका की दो महिला कर्मी, एक घंटे तक रही जान सांसत में

सीवान,एजेंसी। मॉडल सदर अस्पताल में रविवार की सुबह बिजली कटते ही जीविका की दो महिला कर्मी लिफ्ट में फंस गयीं. लिफ्ट का पावर बैकअप फेल होने के कारण वह पहली और दूसरी मंजिल के बीच जाकर रुक गयी। लिफ्ट में फंसी दोनों महिलाओं के मोबाइल में नेटवर्क नहीं होने के कारण वे किसी को फोन कर मदद भी नहीं मांग सकीं। करीब एक घंटे तक दोनों महिलाएं लिफ्ट के अंदर फंसी रहीं। बताया जाता है कि दोनों महिला कर्मी रविवार की सुबह करीब आठ बजे ड्यूटी के लिए अस्पताल पहुंची थीं। लिफ्ट से ऊपर जा रही थीं, तभी अचानक बिजली गुल हो गयी। पावर बैकअप काम नहीं करने के कारण लिफ्ट बीच में ही रुक गयी। करीब 10 मिनट बाद अस्पताल की बिजली आपूर्ति बहाल हुई, लेकिन लिफ्ट फिर भी चालू नहीं हुई। इसके बाद दोनों महिलाओं ने लिफ्ट के अंदर से शोर मचाना शुरू किया। सफाई कार्य में लगे कर्मियों को आवाज सुनायी दी तो उन्हें लिफ्ट में किसी के फंसे होने का पता चला।

अस्पताल के कर्मचारियों ने लिफ्ट को चालू करने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि आपात स्थिति में लिफ्ट खोलने की जिम्मेदारी किसकी है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। काफी देर तक प्रयास के बाद बगल में बन रहे एमसीएच भवन के निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को इसकी सूचना दी गयी। करीब एक घंटे बाद निर्माण कार्य में लगा एक कर्मचारी मौके पर पहुंचा और चाबी की मदद से लिफ्ट का गेट खोलकर दोनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। मॉडल सदर अस्पताल भवन का निर्माण बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) द्वारा

कराया गया है। निर्माण के बाद तीन साल तक लिफ्ट समेत अन्य उपकरणों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी बीएमएसआईसीएल की बतायी जा रही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लिफ्ट में बार-बार खराबी आने और इसके रखरखाव को लेकर बीएमएसआईसीएल के अधिकारियों को कई बार पत्र भेजा गया है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि शनिवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में भी मॉडल सदर अस्पताल की लिफ्ट का मामला उठा था। इस दौरान डीएम स्तर से बीएमएसआईसीएल के डीजीएम से लिफ्ट की स्थिति को लेकर जवाब मांगा गया है। इसके अगले ही दिन लिफ्ट में दो महिला कर्मियों के फंसने की घटना ने अस्पताल की लिफ्ट के रखरखाव और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिये हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि लिफ्ट की एक चाबी अस्पताल प्रशासन के पास है. घटना के बाद अब ऑन-ड्यूटी सुरक्षाकर्मियों को भी लिफ्ट की चाबी उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि भविष्य में आपात स्थिति में लिफ्ट में फंसे लोगों को तत्काल बाहर निकाला जा सके। उन्होंने बताया कि लिफ्ट की मरम्मत और रखरखाव के लिए बीएमएसआईसीएल के अधिकारियों को कई बार पत्राचार किया गया है।

मधेपुरा रेल फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, बोले— 'योग्यता के अनुसार नौकरी दो, नहीं तो फैक्ट्री बंद करो

मधेपुरा,एजेंसी। बिहार के मधेपुरा की रेल इंजन फैक्ट्री को लेकर आसपास के ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर रोजगार के मामले में अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर फैक्ट्री खड़ी है, उसका लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलना चाहिए। उनकी मांग है कि 'योग्यता के अनुसार फैक्ट्री में नौकरी दो, स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, नहीं तो फैक्ट्री बंद करो। दरअसल, हाल ही में अलस्टॉम और भारतीय रेलवे की संयुक्त कंपनी एमईएलपीएल की एक रिपोर्ट पटना में जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव परियोजना ने वित्तीय वर्ष 2020-26 के दौरान देशभर में करीब 60 हजार करोड़ रुपये के आर्थिक आउटपुट को सपोर्ट किया है। रिपोर्ट और मीडिया में स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की बात सामने आने के बाद फैक्ट्री के आसपास के गांवों में नाराजगी और बढ़ गई।

ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री में स्थानीय युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि यहां रेल इंजन के निर्माण के नाम पर बाहर से सामान लाकर सिर्फ असेंबलिंग की जाती है। उनका कहना है कि यदि स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे कल-पुर्जों तक का निर्माण होता, तो आसपास के लोगों को रोजगार

और व्यवसाय का बड़ा अवसर मिलता। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीण अरविंद कुमार यादव ने फैक्ट्री के एक अधिकारी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी गांव के युवाओं से कथित तौर पर स्मैक बिकवा रहे हैं और इससे समाज बर्बाद हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बच्चों ने आईटीआई की पढ़ाई की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें योग्यता के मुताबिक रोजगार नहीं मिला। इन आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सुधीर कुमार यादव ने कहा कि रोजगार के साथ-साथ बिजली, शिक्षा और किसानों की सुविधाओं को लेकर भी ग्रामीणों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। उनका कहना है कि योग्य युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि जिसकी जैसी डिग्री और तकनीकी योग्यता हो, उसे उसी के अनुरूप नौकरी दी जाए। अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि जमीन लेते समय स्थानीय विकास और रोजगार का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज भी गांव के कई युवा बाहर कमाने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि फैक्ट्री मधेपुरा में है, जमीन मधेपुरा की है, तो रिपोर्ट पटना में क्यों जारी की गई? उनका कहना है कि कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर होता तो ग्रामीणों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता। फिलहाल ग्रामीणों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की बात कही है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे एक बार फिर बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। वही इस संबंध में फैक्ट्री प्रबंधन ने किसी भी प्रकार का बयान देने से परहेज किया।

भागलपुर में बाढ़ का कहर, 9 प्रखंडों के 45 गांव जलमग्न, राहत कार्यों पर सांसद की सीधी नजर

भागलपुर। जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। गंगा और अन्य सहायक नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण 9 प्रखंडों की 28 पंचायतों के 45 गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इस आपदा से 11,320 परिवार और करीब 48,081 लोग प्रभावित हुए हैं। स्थानीय सांसद बाढ़ की स्थिति और राहत-बचाव कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वे जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर प्रभावितों तक हर संभव सहायता पहुँचाने में जुटे हैं।

जिला प्रशासन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, आपदा प्रबंधन टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए अब तक 17,776 लोगों को बाढ़ ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। आवागमन और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 51 सरकारी नावें चलाई जा रही हैं। बाढ़ पीड़ितों की भूख मिटाने के लिए प्रशासन द्वारा 6 सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अब तक 75,953 लोगों को भोजन कराया जा चुका है। इसके साथ ही, बेघर हुए जरूरतमंद परिवारों के बीच 3,000 पॉलीथिन शीट बांटी गई हैं। बाढ़ जनित बीमारियों से बचाव के लिए प्रभावित इलाकों में 2 विशेष स्वास्थ्य केंद्र भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इंसानों के साथ-साथ मवेशियों के चारे का संकट भी गहरा गया है। प्रशासन की ओर से अब तक 4,207 क्विंटल पशुचारा प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराया गया है, ताकि मवेशियों को भुखमरी से बचाया जा सके। राघोपुर पंचायत के प्रभावित गांवों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। यहाँ सबसे

अधिक 14,382 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। सामुदायिक रसोई और पशुचारे की व्यवस्था की गई है।

नाथनगर में बाढ़ की भारी मार झेल रहे इस प्रखंड से 2,894 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लोगों के आवागमन और राहत सामग्री पहुँचाने के लिए 17 नावें काम पर लगाई गई हैं। नारायणपुर में प्रभावित गांवों में 5 नावें चलाई जा रही हैं और अब तक 500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सबौर में जलमग्न गांवों में 6 नावें राहत कार्य में जुटी हैं। यहाँ बीमार लोगों के इलाज के लिए 2 स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह सक्रिय हैं। अन्य प्रखंडों में राहत और बचाव कार्य के लिए रंगरा में 6, कहलगांव में 5, पीरपैंती में 3 और गोपालपुर में 1 नाव लगातार प्रभावित क्षेत्रों में फेरे लगा रही है। वहीं सांसद अजय कुमार मंडल ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए हम जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम के साथ लगातार संपर्क में हैं। हर प्रभावित परिवार तक मदद पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। स्थिति पर पल-पल की नजर रखी जा रही है और आवश्यकतानुसार राहत कार्यों का दायरा और बढ़ाया जाएगा।

एक नजर

दलीप ट्रॉफी फाइनल : ईशान किशन की शतकीय पारी से मजबूत स्थिति में ईस्ट जोन

चेन्नई,एजेंसी। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी-2026 के फाइनल मुकाबले के पहले दिन ईस्ट जोन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए साउथ जोन के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली। दिन का खेल समाप्त होने तक ईस्ट जोन ने चार विकेट पर 385 रन बना लिए हैं। कप्तान एवं स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन 111 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि कुमार कुशाग्र 63 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। फाइनल में टॉस जीतकर ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टीम ने आक्रामक अंदाज में शुरुआत की। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तेजतर्रार पारी खेलते हुए 37 गेंदों पर 44 रन बनाए, हालांकि वह अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके। इसके बाद अभिमन्यु ईश्वरन ने मोर्चा संभाला और 86 गेंदों पर 72 रनों की उपयोगी पारी खेली। ईस्ट जोन के बल्लेबाजों ने साउथ जोन के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। शिखर मोहन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 85 रन बनाए। उन्होंने कप्तान ईशान किशन के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। शिखर के आउट होने तक ईस्ट जोन का स्कोर 241 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद कप्तान ईशान किशन और कुमार कुशाग्र ने टीम को बड़े स्कोर की ओर तेजी से आगे बढ़ाया। कुशाग्र ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए टीम को 350 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। ईशान किशन ने कप्तानी पारी खेलते हुए शानदार शतक पूरा किया। उन्होंने 122 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। इससे पहले उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने 4,000 रन भी पूरे कर लिए। किशन की आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी पारी ने ईस्ट जोन को फाइनल के पहले ही दिन मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। पहले दिन का खेल पूरी तरह ईस्ट जोन के नाम रहा। टीम के बल्लेबाजों ने साउथ जोन के गेंदबाजों को पूरे दिन दबाव में रखा।

सूरत में 89वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में दिखा फिटनेस और नशामुक्ति का जोश

सूरत,एजेंसी। देशभर में स्वस्थ, सक्रिय और नशामुक्त जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 89वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का मुख्य आयोजन रविवार को गुजरात के सूरत में 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' थीम के साथ किया गया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों, फिटनेस प्रेमियों, विद्यार्थियों, युवाओं और आम नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'फिट इंडिया' आंदोलन के परिणामस्वरूप देशभर में 'संडेज ऑन साइकिल' अभियान ने व्यापक रूप लिया है। उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र के लिए स्वस्थ आबादी आवश्यक है और साइकिलिंग स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने के कई फायदे हैं। यह प्रभावी व्यायाम का माध्यम है, 'नशा मुक्त भारत' अभियान को मजबूती देता है, प्रदूषण कम करने में मदद करता है और ईंधन की खपत घटाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है। मांडविया ने लोगों से अपील की कि साइकिलिंग को केवल रविवार तक सीमित न रखा जाए बल्कि इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए। विशेष रूप से आसपास के कार्यस्थलों तक आने-जाने के लिए साइकिल का उपयोग करने से 'फिट इंडिया' के संकल्प को और मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं को नशे से दूर रहने और 'नशा मुक्त भारत' के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। सूरत में साइकिल कार्यक्रम की शुरुआत सुबह मांगढ़ चौक स्थित सरदार पटेल प्रतिमा से हुई। प्रतिभागियों ने योग, जुंबा और विभिन्न फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लिया। इसके बाद करीब 6 किलोमीटर की साइकिल राइड सरथाना जू तक निकाली गई। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 89वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम में युवाओं के जीवन और करियर को दिशा देने वाले शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों के अमूल्य योगदान का सम्मान किया गया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने हिस्सा लिया।

वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 : अहमदाबाद में प्रतियोगिता का आगाज

अहमदाबाद,एजेंसी। गुजरात के प्रसिद्ध साबरमती रिवरफ्रंट पर रविवार को वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 की प्रतियोगिता का आधिकारिक आगाज हुआ। आधिकारिक अभ्यास और उपकरणों की जांच के बाद तीरंदाजों ने प्रतियोगिता के मुकाबलों में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के पहले दिन पैरा रिकर्व क्वालिफिकेशन राउंड और व्यक्तिगत एलिमिनेशन राउंड आयोजित किए गए। पुरुष और महिला रिकर्व वर्गों में कुल 39 तीरंदाजों ने हिस्सा लिया, जिनमें भारत के आठ तीरंदाज शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता की शुरुआत शानदार प्रदर्शन के साथ की। हरविंदर सिंह ने पैरा रिकर्व पुरुष क्वालिफिकेशन में 20 तीरंदाजों के बीच तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं महिला वर्ग में भावना ने 19 तीरंदाजों के बीच तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत के सभी आठ तीरंदाज अगले दौर में पहुंच गए हैं। पुरुष वर्ग में हरविंदर सिंह, परवीन, सहजवीर सिंह और विजय सुंडी, जबकि महिला वर्ग में भावना, पूजा कुमारी, राजश्री धनराज राठौड़ और पूजा ने अगले चरण में जगह बनाई। महिला क्वालिफिकेशन में इंडोनेशिया शीर्ष पर रहा, जबकि पुरुष क्वालिफिकेशन में ईरान ने पहला स्थान हासिल किया। इससे प्रतियोगिता के अगले चरण के मुकाबलों के लिए तस्वीर साफ हो गई है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन पैरा कंपाउंड वर्ग के तीरंदाज मैदान में उतरेंगे। भारत की ओर से शीटल देवी, पायल नाग और राकेश कुमार सहित प्रमुख तीरंदाज अपनी चुनौती पेश करेंगे। पहले दिन के मुकाबलों के साथ प्रतियोगिता अब निर्णायक चरण की ओर बढ़ रही है।

सात्विक-चिराग ने पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय बैडमिंटन की स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने रविवार को इतिहास रचते हुए चाइना मास्टर्स-2026 का पुरुष युगल खिताब अपने नाम कर लिया। चीन के शेन्जेन एरिना में खेले गए फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन की हे जी टिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी को तीन गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 11-21, 21-13, 21-17 से शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले 2023 और 2025 में इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन दोनों मौकों पर उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा था। इस बार भारतीय जोड़ी ने फाइनल की बाधा पार करते हुए पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया।

मुकाबले में सात्विक-चिराग की जोड़ी ने धीमी शुरुआत के बाद शानदार वापसी की और निर्णायक गेम में बेहतरीन संयम दिखाते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। करीब 70 मिनट तक चले मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने चीन की जोड़ी की चुनौती का डटकर सामना किया। पहले गेम में हे जी टिंग और रेन जियांग यू ने आक्रामक शुरुआत की। चीनी जोड़ी ने अपनी तेज गति और सटीक शॉट्स के दम पर भारतीय खिलाड़ियों पर लगातार दबाव बनाए रखा। सात्विक और चिराग अपनी लय हासिल करने के लिए संघर्ष करते नजर आए और पहला गेम 11-21 से गंवा बैठे। दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने जोरदार वापसी की। सात्विक और चिराग ने आक्रामक खेल के साथ अपने डिफेंस को भी बेहतर किया और दूसरा गेम 21-13 से जीतकर मुकाबले को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। निर्णायक गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। मुकाबला 17-17 की बराबरी पर पहुंचने के बाद भारतीय जोड़ी ने दबाव के क्षणों में शानदार संयम दिखाया। सात्विक और चिराग ने लगातार महत्वपूर्ण प्वाइंट हासिल करते हुए निर्णायक गेम 21-17 से अपने नाम किया और खिताब जीत लिया। यह 2026 सत्र में सात्विक और चिराग का दूसरा खिताब है। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 का खिताब जीता था। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) ने सोशल मीडिया एक्स पर दोनों खिलाड़ियों की जीत पर खुशी जताते हुए लिखा, सात्विक-चिराग के लिए ऐतिहासिक जीत। दोनों ने शानदार वापसी करते हुए अपना पहला चाइना मास्टर्स खिताब जीता। यह 2026 में उनका दूसरा सुपर 750 खिताब और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। दो बार रनर-अप रहने के बाद चाइना मास्टर्स में तीसरी बार उन्हें जीत मिली।

आयरलैंड महिला टीम की ऑलराउंडर अर्लीन केली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया

नई दिल्ली। आयरलैंड महिला टीम की ऑलराउंडर अर्लीन केली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ वॉर्सेस्टर (इंग्लैंड) में रविवार को खेला जा रहा तीसरा वनडे मैच उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच है।

32 वर्षीय केली ने जून, 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और आयरलैंड के लिए सभी फॉर्मेट में 110 मैच खेले, जिससे वह टीम की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक बन गईं। उन्होंने आयरलैंड के लिए 136 विकेट के साथ अपना करियर खत्म किया। केली ने बल्ले से भी अच्छा योगदान दिया और व्हाइट-बॉल क्रिकेट में 600 से अधिक रन बनाए। क्रिकेट आयरलैंड की ओर से जारी बयान में केली ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात रही है और मैं खुशकिस्मत रही हूं कि मुझे मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह कई अद्भुत यादें बनाने का मौका मिला है। अब खेल से संन्यास लेने और अपने परिवार व दोस्तों के पास रहने के लिए न्यूजीलैंड लौटने का सही समय आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं क्रिकेट आयरलैंड, अपने सभी कोचों और अपनी टीम की साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। आप लोगों ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया और मुझे वैसा ही रहने दिया जैसी मैं हूं। इस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत खास रहा है और मुझे पता है कि यह ग्रुप बहुत कुछ हासिल करने की काबिलियत रखता है। मैं टीम को लगातार फॉलो करती रहूंगी और समर्थन करती रहूंगी। आयरलैंड की कप्तान गैबी लुईस ने केली की तारीफ करते हुए कहा कि वह ऐसी खिलाड़ी हैं, जिन पर टीम हमेशा भरोसा कर सकती थी। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में अर्लीन हमारी टीम का एक बहुत खास हिस्सा बन गई थीं। उन्होंने मैदान के अंदर और बाहर, दोनों ही जगह हमें बहुत कुछ दिया है और वह ऐसी इंसान रही हैं जिन पर हम हमेशा भरोसा कर सकते थे। लुईस ने कहा कि हम जानते हैं कि इतने लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहना उनके लिए कितना मुश्किल रहा है। भले ही हमें उनकी बहुत याद आएगी, लेकिन हम इस बात से बहुत खुश हैं कि वह घर लौट रही हैं और अपने चाहने वालों के करीब जा रही हैं। पिछले चार साल में उन्होंने हमें जो कुछ भी दिया है, उसके लिए हम अर्लीन का जितना भी शुक्रिया अदा करें, कम है। उन्होंने हमारी टीम पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है और वह हमेशा हमारी आयरिश क्रिकेट फैमिली का एक अहम हिस्सा रहेंगी।

बांदा मिनी ओलंपिक का भव्य समापन, खिलाड़ियों की जीत पर गूंजा इंडोर हाल

बांदा। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में खेलों के रोमांच, खिलाड़ियों के जोश और दर्शकों की गगनभेदी तालियों के बीच रविवार को बांदा मिनी ओलंपिक के प्रथम चरण का भव्य समापन हुआ। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंडोर हाल में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी अमित आसेरी ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों, अभिभावकों और खेलप्रेमियों की बड़ी संख्या मौजूद रही। समापन समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अमित आसेरी ने युवाओं से नशे जैसे दुर्व्यसनों से दूर रहने और खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेल शरीर को स्वस्थ रखने के साथ मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। उन्होंने सफल आयोजन के लिए खिलाड़ियों, आयोजकों और सहयोगियों को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए भविष्य में भी ऐसे आयोजन लगातार किए जाएंगे।

समापन समारोह के दौरान कबड्डी का फाइनल मुकाबला खास आकर्षण का केंद्र रहा। जेएन योद्धा और जेएन कॉलेज के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में जेएन योद्धा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40-26 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम कर लिया। महिला और पुरुष वर्ग की रस्साकसी प्रतियोगिताओं में भी खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। जोरदार मुकाबलों के दौरान दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था और इंडोर हाल लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। समारोह में उस समय खासा उत्साह देखने को मिला, जब बांदा मिनी ओलंपिक का शुभंकर पांडा अपने साथी भालू दादा के साथ इंडोर हाल में पहुंचा। दोनों शुभंकरों की एंट्री होते ही दर्शकों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया और पूरा हाल उत्साह से भर उठा। जिलाधिकारी ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आदर्श राय के नेतृत्व वाली वालीबाल सीनियर पुरुष वर्ग की विजेता बांदा स्टेडियम टीम के खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बैडमिंटन पुरुष एकल ओपन वर्ग में अजफर ने स्वर्ण और अर्श सईद ने रजत पदक जीता। महिला ओपन एकल में गौरी को स्वर्ण और मांडवी को रजत पदक मिला। अंडर-15 बालिका एकल में अपूर्वा को स्वर्ण तथा गरिमा को रजत पदक प्रदान किया गया।

देहरादून टी-20 लीग के रोमांचक मुकाबलों में मसूरी थंडर और हरबर्टपुर नाइट राइडर्स ने दर्ज की जीत

देहरादून,एजेंसी। देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में खेली जा रही देहरादून टी-20 लीग में रविवार को एक बार फिर रोमांच से भरपूर मुकाबले देखने को मिले। दिन के पहले मुकाबले में मसूरी थंडर ने ऋषिकेश ड्रैगन्स को 17 रनों से मात दी, जबकि दूसरे मैच में हरबर्टपुर नाइट राइडर्स ने विकासनगर धमाका को 12 रनों से शिकस्त देकर जीत दर्ज की। दिन के पहले मैच में ऋषिकेश ड्रैगन्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मसूरी थंडर की शुरुआत खराब रही और सलामी बल्लेबाज आर्यन गोदियाल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इसके बाद एलन चेतन ने 25 गेंदों में 41 रन बनाए। मध्यक्रम में आयुष चौहान ने 24 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली और अंतिम ओवरों में अनमोल शाह ने 22 गेंदों में 35 रन बनाकर टीम का स्कोर 20 ओवरों में 9 विकेट पर 163 रन तक पहुंचाया। ऋषिकेश ड्रैगन्स की तरफ से युवराज चौधरी ने 4 ओवरों में 24 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि कप्तान तेजिंदर सिंह और मुकुल नागर को 2-2 सफलताएं मिलीं।

इसके बाद 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऋषिकेश ड्रैगन्स की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और 37 रन तक पहुंचते-पहुंचते टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद कमल सिंह ने एक छोर संभाले रखा और 33 गेंदों में 53 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर मैच में रोमांच बनाए रखा। दूसरे छोर से युवराज चौधरी ने भी 32 रनों का योगदान दिया, लेकिन 129 रन के कुल स्कोर पर कमल सिंह के आउट होते ही ऋषिकेश की उम्मीदें टूट गईं। मसूरी थंडर के गेंदबाजों ने कसी हुई

गेंदबाजी करते हुए ऋषिकेश की पूरी टीम को 19.2 ओवरों में 146 रनों पर ढेर कर दिया। मसूरी की ओर से अनमोल शाह, अंशुल कुमार और दीपेश ने 2-2 विकेट हासिल कर अपनी टीम को 17 रनों से एक यादगार जीत दिला दी। दिन के दूसरे मुकाबले में विकासनगर धमाका ने टॉस जीतकर हरबर्टपुर नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। हरबर्टपुर की शुरुआत बेहद धीमी रही और 39 रन के स्कोर तक उसके 3 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद कुणाल वी. सिंह (34 रन) और सचिथ जे ने पारी को संभाला। सचिथ जे ने मैदान के हर कोने में चौके-छक्के बरसाते हुए महज 39 गेंदों पर 4 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 70 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी के बल पर हरबर्टपुर की टीम 19.5 ओवरों में 176 रन बनाकर ऑलआउट हुई। विकासनगर की ओर से अभिषेक सिंह ने 3 विकेट झटके, जबकि जनमेजय जोशी को 2 विकेट मिले। 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी विकासनगर धमाका की शुरुआत भी खराब रही और 41 रन पर ही टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद विशाल डंगवाल (32) और शाश्वत डंगवाल (31) ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, वहीं प्रशांत चौहान ने भी 23 रनों का योगदान दिया। हालांकि, हरबर्टपुर के गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकालकर विकासनगर पर दबाव बनाए रखा। हरबर्टपुर के गेंदबाज अक्षय थापली ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3 ओवरों में 18 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जबकि गौरव चौधरी ने 3 विकेट हासिल किए। पूरी विकासनगर टीम 19.5 ओवरों में 164 रनों पर ढेर हो गई और हरबर्टपुर नाइट राइडर्स ने 12 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

बारासात में दो दशक बाद डर्बी का रोमांच, पुलिस ने बताया पूरा सुरक्षा प्लान

कोलकाता,एजेंसी। करीब दो दशक के लंबे अंतराल के बाद उत्तर 24 परगना जिले के मुख्यालय बारासात में एक बार फिर फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबलों में शुमार डर्बी मैच का रोमांच देखने को मिलेगा। सोमवार, सात सितंबर को बारासात के विद्यासागर क्रीड़ांगन में कोलकाता मैदान के दो दिग्गज क्लब ईस्ट बंगाल और मोहन बागान आमने-सामने होंगे। मुकाबले को लेकर दोनों क्लबों के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। संभावित भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। मैच से पहले रविवार को बारासात पुलिस ने प्रेस वार्ता कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, मैच के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए स्टेडियम और आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। भीड़ नियंत्रण के साथ स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश और निकास पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।

बारासात पुलिस जिले की पुलिस अधीक्षक जे. मार्सी ने बताया कि मैच को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्टेडियम के अंदर दर्शकों की सुरक्षा से लेकर बाहर यातायात नियंत्रण तक हर स्तर पर व्यवस्था की गई है। विद्यासागर क्रीड़ांगन में दर्शकों के बैठने की क्षमता करीब 12 हजार है। हालांकि, ईस्ट बंगाल और मोहन बागान जैसे लोकप्रिय क्लबों के बीच डर्बी मुकाबले को देखते हुए 20 हजार से अधिक समर्थकों के बारासात पहुंचने की संभावना है। ऐसे में स्टेडियम की क्षमता से अधिक संभावित भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। पुलिस ने समर्थकों से निर्धारित नियमों का पालन करने और बिना टिकट स्टेडियम के आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने की अपील की है। स्टेडियम में प्रवेश के दौरान सुरक्षा जांच भी की जाएगी। दर्शकों की सुविधा के लिए स्टेडियम परिसर में पेयजल और चिकित्सा व्यवस्था की गई है, ताकि आपात स्थिति में

तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

बड़ी संख्या में समर्थकों के वाहनों से बारासात पहुंचने की संभावना को देखते हुए पार्किंग की भी अलग व्यवस्था की गई है। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल समर्थकों के वाहनों के लिए कचहरी मैदान और किशलय होम के मैदान को पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है। मैच के मद्देनजर सोमवार दोपहर तीन बजे से बारासात के केएनसी रोड पर आम लोगों के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पुलिस के अनुसार, यह व्यवस्था संभावित भीड़ और यातायात के दबाव को नियंत्रित करने के लिए की गई है। मैच सोमवार को होने के कारण स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और अदालतों में सामान्य गतिविधियां भी जारी रहेंगी। ऐसे में पुलिस के सामने मैच की भीड़ के साथ-साथ नियमित यातायात को सुचारु बनाए रखने की भी चुनौती होगी। विद्यासागर क्रीड़ांगन के आसपास कई महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान स्थित हैं। इनमें बारासात पीरीचरण गवर्नमेंट स्कूल, कालीकृष्ण स्कूल, गर्ल्स स्कूल सहित दो अन्य प्राथमिक विद्यालय और बारासात गवर्नमेंट कॉलेज शामिल हैं। इन संस्थानों में अर्धवार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं भी चल रही हैं। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि मैच के दौरान माइक से होने वाली घोषणाओं, सुरक्षा निर्देशों और समर्थकों की आवाजाही से परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज आने-जाने वाले विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी यातायात संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर पुलिस और प्रशासन के सामने 12 हजार दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम के आसपास संभावित 20 हजार से अधिक समर्थकों की भीड़, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को संभालना सबसे बड़ी चुनौती है।

एक नजर

ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिकी मिसाइल से हमला

तेहरान,एजेंसी। फारस की खाड़ी में खार्ग द्वीप के पास एक छोटे ईरानी तेल टैंकर को अमेरिकी सेना की मिसाइल ने निशाना बनाया। फिलहाल, इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडोलू और ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तसनीम न्यूज़ के अनुसार, घटना खार्ग द्वीप से करीब छह नॉटिकल मील दूर हुई। तसनीम ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया कि लंगर डाले हुए टैंकर पर अमेरिकी सेना की ओर से दागे गए करीब चार प्रोजेक्टाइल लगे। रिपोर्ट के मुताबिक, हमले के बाद टैंकर के क्रू मेंबर्स को जहाज से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। स्थानीय सूत्रों ने दावा किया कि घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। अधिकारियों की ओर से फिलहाल टैंकर को हुए नुकसान की सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। संबंधित एजेंसियां घटना की परिस्थितियों और नुकसान की सीमा की जांच कर रही हैं। फिलहाल, अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इस कथित मिसाइल हमले पर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए टैंकर पर हमले से जुड़ी जानकारी को फिलहाल ईरानी मीडिया और स्थानीय सूत्रों के दावे के रूप में देखा जा रहा है। खार्ग द्वीप ईरान के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यह देश के प्रमुख कच्चे तेल निर्यात टर्मिनलों में शामिल है और ईरान के समुद्री तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा यहीं से संचालित होता है। इसी रणनीतिक महत्व के कारण फारस की खाड़ी में किसी भी सैन्य गतिविधि का असर क्षेत्रीय तेल आपूर्ति और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ने की आशंका रहती है।

अमेरिका ने दी सऊदी अरब को 5 अरब डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी

वॉशिंगटन,एजेंसी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने सऊदी अरब को करीब 5 अरब डॉलर के हथियार और सैन्य उपकरण बेचने की मंजूरी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, इस प्रस्तावित सौदे से सऊदी अरब की हवाई सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी और वह क्षेत्रीय खतरों से बेहतर तरीके से निपट सकेगा। जिओ न्यूज ने अमेरिकी विदेश विभाग के हवाले से बताया कि प्रस्तावित बिक्री में बम, गाइडेंस किट और अन्य सैन्य उपकरण शामिल हैं। विभाग के अनुसार, इससे सऊदी अरब की घरेलू सुरक्षा मजबूत होने के साथ-साथ अमेरिकी सेना और खाड़ी क्षेत्र के सहयोगी देशों की सैन्य प्रणालियों के साथ उसकी इंटरऑपरेबिलिटी भी बेहतर होगी। अमेरिका ने सऊदी अरब को करीब 750 मिलियन डॉलर के एजीटी-1500 इंजन बेचने की भी मंजूरी दी है। इस सौदे के लिए अमेरिकी कंपनी हनीवेल मुख्य ठेकेदार होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि सऊदी अरब एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी है और उसकी सुरक्षा क्षमता मजबूत करना अमेरिका की विदेश नीति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है। यह हथियार सौदा ऐसे समय हुआ है जब मध्य पूर्व में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, संघर्ष शुरू होने के बाद ईरानी सेना और यमन के हूथी विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब को ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा है। वाशिंगटन का कहना है कि प्रस्तावित हथियार बिक्री से रियाद को मौजूदा और भविष्य के क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों से निपटने में मदद मिलेगी।

उरुग्वे में एवियन इन्फ्लूएंजा की दस्तक, एच5 वायरस मिलने पर हेल्थ इमरजेंसी घोषित

मोंटेवीडियो,एजेंसी। उरुग्वे में घरेलू पोल्ट्री में अत्यधिक रोगजनक H5 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस मिलने के बाद सरकार ने देशभर में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। अधिकारियों ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पोल्ट्री की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाने के साथ पक्षियों से जुड़े मेलों, नीलामी और सार्वजनिक प्रदर्शनियों पर भी रोक लगा दी है। तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडोलू के मुताबिक पशुधन, कृषि और मत्स्य पालन मंत्रालय के तहत पशुधन सेवा महानिदेशालय ने दक्षिण-पश्चिमी कोलोनिया क्षेत्र में एवियन इन्फ्लूएंजा के संक्रमण की पुष्टि की। अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में पक्षियों की मौत के बाद जांच शुरू की गई थी। शुरुआती रैपिड टेस्ट में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बाद में सरकारी प्रयोगशाला की जांच में H5 वायरस की मौजूदगी सामने आई। आपातकालीन आदेश के तहत प्रभावित क्षेत्र में प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। बिना व्यावसायिक उद्देश्य के पाले जाने वाले पक्षियों की घरेलू आवाजाही पर रोक लगाई गई है। हालांकि, सरकारी पोल्ट्री निगरानी प्रणाली में पंजीकृत पक्षियों को कुछ परिस्थितियों में इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। वहीं, अधिकारियों ने घरों में खुले तौर पर घूमने वाले पक्षियों को बंद और ढकी हुई जगहों में रखने का निर्देश दिया है, ताकि उनका संपर्क जंगली पक्षियों से न हो। स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रभावित स्थान पर संक्रमित या संपर्क में आए पक्षियों को मारने और सुरक्षित तरीके से नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अमेरिकी सैन्य डॉक्टर का कोर्ट में दावा- कोरोना टीके से हुई 28 सैनिकों की मौत

वॉशिंगटन,एजेंसी। अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अमेरिकी सेना की डॉक्टर थेरेसा लॉन्ग ने वर्जीनिया की एक फेडरल कोर्ट में दिए बयान में कहा है कि वह ऐसे मामलों की जांच कर रही हैं, जिनमें अमेरिकी सैन्यकर्मियों की मौत को कोरोना के टीके से संभावित रूप से जोड़ा गया है। रूस के टेलीविजन नेटवर्क रशिया टुडे ने बीते 14 अगस्त को कोर्ट में दिए गए बयान का हवाला देते हुए बताया कि लॉन्ग 2,544 ऐसी मौतों की समीक्षा कर रही हैं, जिन्हें वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम (वीएआरईएस) में दर्ज किया गया था। ये मामले फिलहाल अपुष्ट हैं और जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि इनमें से कितनी मौतों का वास्तव में वैक्सीन से कोई संबंध था। रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्ग ने कोर्ट में यह भी कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से 28 ऐसे लोगों के बारे में जानती हैं, जिनकी मौत को वह कोरोना के टीके से जोड़ती हैं। हालांकि, उन्होंने इन मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं होने की बात कही। लॉन्ग को स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ. केनेडी जूनियर के वरिष्ठ सैन्य चिकित्सा सलाहकार के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। उनके मुताबिक, उन्हें महामारी के दौरान सैन्य स्वास्थ्य निगरानी व्यवस्था और दो सैन्य मेडिकल डेटाबेस की समीक्षा का जिम्मा दिया गया है। उन्होंने इस जांच को करीब एक साल में पूरा करने की उम्मीद जताई है। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना

जरूरी है। वीएआरईएस में किसी स्वास्थ्य समस्या या मौत की रिपोर्ट दर्ज होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह घटना टीके के कारण हुई। वीएआरईएस एक निगरानी प्रणाली है, जिसमें टीकाकरण के बाद सामने आने वाली घटनाओं की रिपोर्ट जमा की जाती है। कारण-सम्बंध स्थापित करने के लिए अलग से चिकित्सकीय और वैज्ञानिक जांच जरूरी होती है। इसलिए 2,544 का आंकड़ा 'टीके से हुई 2,544 मौतें' नहीं माना जा सकता। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार ये ऐसी मौतों की रिपोर्ट हैं जिनकी वजह और टीके के बीच संभावित संबंध की जांच की जा रही है।

लॉन्ग की गवाही पूर्व सैन्य स्वास्थ्य अधिकारी टेरी एडिरिम से जुड़े एक मुकदमे के दौरान सामने आई। एडिरिम ने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया, जबकि सीआईए का पक्ष है कि मामला रोजगार और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवाद का है। लॉन्ग ने इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से गवाही दी। कोरोना महामारी के दौरान अमेरिकी सेना में टीकाकरण को लेकर अनिवार्य नीति लागू की गई थी। टीके से इनकार करने वाले हजारों सैन्यकर्मियों को सेवा से अलग किया गया। बाद में अमेरिकी सरकार ने इस नीति को समाप्त किया और टीका न लेने के कारण हटाए गए सैन्यकर्मियों की बहाली का रास्ता खोला।

बांग्लादेश में खसरे का कहर, एक हजार के करीब पहुंची बच्चों की मौत

ढाका। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। देश में मार्च से अब तक खसरे और खसरे जैसे लक्षणों से 987 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अकेले पिछले 24 घंटों में 1,114 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। मृतकों में बड़ी संख्या बच्चों की है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि यह प्रकोप दशकों में देश में सामने आए सबसे गंभीर खसरा संकटों में से एक बन गया है।

बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संगबाद संस्था (बीएसएस) तथा ताइवान की राष्ट्रीय समाचार सेंट्रल न्यूज एजेंसी (सीएनए) ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के हवाले से बताया कि, 15 मार्च से अब तक संदिग्ध खसरे से 888 बच्चों की मौत हुई है। वहीं, कन्फर्म खसरे से मरने वालों की संख्या 99 है। पिछले 24 घंटों में कन्फर्म खसरे से किसी मौत की सूचना नहीं मिली। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 15 मार्च से अब तक 1,62,262 संदिग्ध खसरे के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 19,567 मामले कन्फर्म हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 40 नए कन्फर्म मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 1,42,453 संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 1,37,350 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी ढाका के बच्चों के अस्पतालों में खसरे से संक्रमित और संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। अस्पताल के खसरा वार्ड में बड़ी संख्या में छोटे बच्चे भर्ती हैं और कई मरीजों को सांस लेने में गंभीर परेशानी के कारण ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। अस्पताल में भर्ती एक छह महीने के बच्चे अयान को पहले निमोनिया के कारण भर्ती कराया गया था। बाद में उसे खसरा हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक, पहले से कमजोर फेफड़ों और कुपोषण के कारण उसकी स्थिति और गंभीर हो गई।

उसे कई दिनों तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। डॉक्टरों का कहना है कि मौजूदा प्रकोप में बड़ी संख्या में छह महीने से पांच साल तक के बच्चे प्रभावित हुए हैं। कई बच्चों में कुपोषण भी पाया गया है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और खसरे की जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। खसरा बेहद संक्रामक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से खांसने और छींकने से फैलती है। गंभीर मामलों में इससे निमोनिया, सांस लेने में कठिनाई और मस्तिष्क में सूजन जैसी जटिलताएं हो सकती हैं।

नेपाल में आपदा प्रभावित 84 हजार लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र जुटाएगा 5 करोड़ डॉलर

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से 84 हजार लोग प्रभावित हुए हैं और उन्हें तत्काल मानवीय सहायता की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और उसके सहयोगी संगठनों ने प्रभावित समुदायों तक जरूरी मदद पहुंचाने के लिए करीब 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता के साझेदार संगठनों से यह राशि उपलब्ध कराने की अपील की है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई बाढ़ तथा भूस्खलन से प्रभावित 84 हजार से अधिक लोगों तक जीवनरक्षक सहायता पहुंचाने के लिए यह अपील की गई है।

नेपाल में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के मुताबिक, यह सहायता राशि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में नेपाल सरकार द्वारा तैयार की गई चार महीने की योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने में इस्तेमाल की जाएगी। यह योजना सर्दी शुरू होने से पहले प्रभावित लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए बनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र और उसके मानवीय सहायता साझेदार संगठन नेपाल सरकार द्वारा संचालित बचाव और राहत अभियान के साथ समन्वय करते हुए

काम कर रहे हैं। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र की आवासीय समन्वयक लीला पीटर्स याहिया ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि इस सहायता अपील की मुख्य प्राथमिकता सरकार के नेतृत्व में सर्दी शुरू होने से पहले सबसे दुर्गम बस्तियों तक आश्रय, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छ पानी और नकद सहायता पहुंचाना है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि इस सहायता के जरिए सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में लोगों तक नकद सहायता, भोजन, आश्रय, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य जीवनरक्षक सामग्री पहुंचाई जाएगी। यूएन और उसके साझेदार नेपाल सरकार के साथ समन्वय कर आपदा प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचाने के प्रयास में जुटे हैं। विशेष रूप से सबसे ज्यादा तबाह और दुर्गम समुदायों तक जरूरी सहायता पहुंचाना इस अभियान की प्राथमिकता है।

बालेन्द्र शाह 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित, नेपाल आपदा को लेकर करेंगे अपील

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में नेपाल का प्रतिनिधित्व करते हुए बालेन्द्र शाह 22 सितंबर से अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। नेपाल की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने वक्ताओं की सूची में संशोधन करते हुए शुक्रवार को प्रधानमंत्री शाह के संबोधन का कार्यक्रम तय किया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की ओर से निर्धारित समय की जानकारी न्यूयॉर्क स्थित नेपाली मिशन के जरिए विदेश मंत्रालय होते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री शाह की अमेरिका यात्रा की तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं।

संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, 24 सितंबर को दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक 18 नेता महासभा को संबोधित करेंगे। इस सूची में नेपाल के प्रधानमंत्री 17वें वक्ता होंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सूची के मुताबिक इसी सत्र में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 18वीं वक्ता के रूप में संबोधन करेंगी। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाले महासभा के इस सत्र में अब तक 118 देशों के नेताओं के संबोधन की सूची तैयार की गई है।विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री सचिवालय के अधिकारियों के मुताबिक, नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और आपदा के कारण प्रधानमंत्री शाह के स्वयं महासभा को संबोधित करने की तैयारी की गई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल के समक्ष भीषण आपदा और इससे हुए नुकसान के लिए

क्षतिपूर्ति तथा जलवायु न्याय का मुद्दा उठाएंगे। साथ ही नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए इस वैश्विक मंच से सहयोग की अपील भी करने वाले हैं। आपदा से पहले महासभा में नेपाल की ओर से विदेश मंत्री शिशिर खनाल के संबोधन की तैयारी थी। हालांकि, अब प्रधानमंत्री शाह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जाएगा। सरकार की कोशिश है कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को यथासंभव छोटा रखा जाए। नेपाल में अभी राहत और बचाव कार्य जारी होने के कारण प्रधानमंत्री के महासभा को संबोधित करने के बाद स्वदेश लौटने की संभावना है। उनके कार्यक्रम के आधार पर ही 'साइडलाइन' द्विपक्षीय बैठकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री की संभावित मुलाकातों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाक़ात का प्रयास किया जा रहा है।प्रधानमंत्री बनने के करीब पांच महीने बाद शाह की यह पहली विदेश यात्रा होगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अबतक किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख के साथ प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं की है। इससे पहले 19 अगस्त को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने महासभा में नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री शिशिर खनाल द्वारा किए जाने का फैसला किया था। लेकिन 26 अगस्त को रसुवा के भोटेकोशी में आई महाविपदा के बाद 3 सितंबर को प्रधानमंत्री शाह के स्वयं महासभा को संबोधित करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री के जाने के कारण विदेश मंत्री खनाल प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में उनके मुख्य सलाहकार कुमार बेन, प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा, निजी सचिव प्रदीप परियार और फोटोग्राफर विनय शाक्य शामिल होंगे। इसी तरह विदेश सचिव अमृतबहादुर राई, संयुक्त राष्ट्र मामलों को देखने वाले महाशाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद ढकाल और शिष्टाचार महापाल कुमार राज खरेल भी प्रतिनिधिमंडल में रहेंगे। न्यूयॉर्क स्थित नेपाली स्थायी मिशन के प्रमुख लोक बहादुर थापा भी महासभा में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

व्यापार घाटा घटाने के लिए भारत के साथ निर्यात बढ़ाएगी ढाका सरकार: वाणिज्य मंत्री मुक्तादिर

ढाका,एजेंसी। बांग्लादेश सरकार भारत और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए किसी एक देश पर केंद्रित रणनीति अपनाने के बजाय देश की कुल निर्यात क्षमता बढ़ाने पर जोर देगी। वाणिज्य मंत्री खांडकर अब्दुल मुक्तादिर ने संसद में यह जानकारी दी। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संगबाद संस्था (बीएसएस) के मुताबिक, मंत्री ने जातीय संसद में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान विपक्षी जमात-ए-इस्लामी के सांसद एम. अब्दुल बातेन के पूरक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत और चीन के साथ बांग्लादेश का व्यापार घाटा काफी बड़ा है, लेकिन इसे केवल किसी एक देश से जुड़ी समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हमें किसी एक देश पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी कुल निर्यात क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। मुक्तादिर ने बताया कि सरकार ने निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं वाले कई क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें चमड़ा, जूट, जहाज निर्माण, हल्का इंजीनियरिंग और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में अनुकूल नीतियां बनाने और नए निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, ऐसे उद्योगों को भी विकसित करने की कोशिश हो रही है, जो अभी अपनी पूरी निर्यात क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। वाणिज्य मंत्री के अनुसार, बांग्लादेश और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार का कुल

मूल्य करीब 12.7 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसमें बांग्लादेश भारत को लगभग 1.89 अरब डॉलर का सामान निर्यात करता है, जबकि भारत से होने वाला आयात इससे काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के साथ बांग्लादेश का व्यापार घाटा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में और बढ़ा है। मंत्री ने यह भी कहा कि भारत में बांग्लादेशी उत्पादों के निर्यात की अभी काफी संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन द्विपक्षीय व्यापार में भारतीय पक्ष की ओर से कुछ प्रतिबंध भी हैं। मुक्तादिर ने बताया कि पिछले दो वर्षों में भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में बांग्लादेश की ओर से भी कुछ बाधाएं सामने आई हैं। हाल में बांग्लादेश आए भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है और भारत के साथ निर्यात बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। कहा कि हम कई तरह से कोशिश कर रहे हैं ताकि भविष्य में भारत के साथ हमारा निर्यात और बढ़ाया जा सके। भारत के साथ बड़े व्यापार घाटे पर बोलते हुए मुक्तादिर ने कहा कि निजी क्षेत्र के कारोबारी अपने व्यापारिक हित और लाभ को ध्यान में रखते हुए भारत से विभिन्न वस्तुओं का आयात करते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि व्यापार घाटे को कम करने के लिए केवल आयात घटाने पर निर्भर रहने के बजाय बांग्लादेश को अपनी उत्पादन और निर्यात क्षमता मजबूत करनी होगी, ताकि विदेशी बाजारों में बांग्लादेशी उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके।

ईरान युद्ध के दौरान गोपनीय जानकारी लीक मामले में 50 अमेरिकी अधिकारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट

वाशिंटन,एजेंसी। ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों के रणनीतिक स्टॉक में कमी से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक होने के मामले में अमेरिकी रक्षा विभाग ने जांच तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त में करीब 50 सैन्य और असैन्य अधिकारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। ने द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि जांच के दायरे में जॉइंट स्टाफ के अधिकारी भी शामिल थे। जांचकर्ताओं का मुख्य फोकस ईरान के साथ सैन्य संघर्ष के चलते लंबी दूरी की मिसाइलों और पैट्रियट इंटरसेप्टर की उपलब्धता में कमी से संबंधित गोपनीय जानकारी के लीक होने पर था। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया में एफबीआई शामिल नहीं थी। अमेरिकी सेना ने अपने आंतरिक जांचकर्ताओं के जरिए यह प्रक्रिया पूरी की।

हालांकि, सभी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया गया। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन को इस जांच से बाहर रखा गया। जांचकर्ताओं ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि क्या किसी सरकारी अधिकारी ने विदेशी खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हुए संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा की थी। इसकी वजह यह बताई गई कि संबंधित हथियारों के आंकड़ों तक पहुंच बेहद सीमित अधिकारियों के पास थी। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने जांच या आंतरिक कर्मचारियों से जुड़े मामलों पर टिप्पणी करने से इनकार किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि रक्षा विभाग गोपनीय

जानकारी के अनधिकृत खुलासे को बेहद गंभीरता से लेता है और ऐसे मामलों की उचित जांच की जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी हथियारों के रणनीतिक भंडार में कमी की खबरों को खारिज किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना के पास हथियारों की भारी मात्रा मौजूद है। उन्होंने गोपनीय जानकारी के लीक को देशद्रोहपूर्ण बयान और फेक न्यूज बताया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि लीक के लिए जिम्मेदार लोगों को खोजकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पॉलीग्राफ जांच का संबंध कई अनधिकृत खुलासों से बताया जा रहा है। इनमें 'सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑर्डर्स बुक' के एक हिस्से का लीक होना भी शामिल है। लीक हुए दस्तावेज के अनुसार छह फोर-स्टार सैन्य अधिकारियों ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान को और बढ़ाने पर औपचारिक असहमति जताई थी। अधिकारियों ने कथित तौर पर चेतावनी दी थी कि युद्ध को लंबे समय तक जारी रखना अमेरिकी सैन्य तैयारियों और वैश्विक स्तर पर उसकी क्षमता को कमजोर कर सकता है।

एक नजर

लेक्चरर भर्ती में आरक्षण से वंचित किए जाने के मामले में एनसीएससी का पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस

नई दिल्ली। लेक्चरर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण के लाभ से वंचित किए जाने की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर सात दिनों में जवाब तलब किया है। एनसीएससी के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने एक बयान में कहा कि राज्यसभा सांसद तरुण चुग से पंजाब शिक्षा विभाग में लेक्चरर भर्ती में आरक्षण नीति के कथित गैर-कार्यान्वयन के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अभ्यावेदन में पंजाब शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित 1,013 लेक्चरर पदों की भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण के लाभ से वंचित किए जाने की शिकायत की गई है। आरोप है कि कई विषयों (पंजाबी, कॉमर्स, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भूगोल आदि) में आरक्षण नियमों और निर्धारित रोस्टर प्रणाली का सही ढंग से पालन नहीं किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने इस मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें मामले के तथ्यों, आरोपों पर की गई कार्रवाई तथा संबंधित सभी अभिलेख (भर्ती अधिसूचना एवं आरक्षण रोस्टर सहित) नोटिस प्राप्ति के सात दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब न मिलने पर वह संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है। मकवाणा ने कहा कि लेक्चरर भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण के लाभ से वंचित किए जाने का मामला बेहद गंभीर है। आयोग अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रावधानों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

एलआईसी को आईसीआईसीआई बैंक में 9.99 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की आरबीआई से मिली मंजूरी

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को आईसीआईसीआई बैंक में 9.99 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से मंजूरी मिल गई है। आईसीआईसीआई बैंक ने शेयर बाजार को नियामक फाइलिंग में बताया कि एलआईसी ने आईसीआईसीआई बैंक में 9.99 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई से मंजूरी प्राप्त कर ली है। इस मंजूरी के बाद दोनों के बीच सौदा पूरा करने का रास्ता साफ हो चुका है। आरबीआई की ओर से जारी मंजूरी पत्र 4 सितंबर 2026 को रात 9:09 बजे प्राप्त हुआ है। यह अनुमति मिलने के बाद अब एलआईसी अगले एक साल के भीतर बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकेगी। आरबीआई की इस अप्रूवल में 9.99 फीसदी हिस्सेदारी के लिए आईसीआईसीआई बैंक के पेड अप शेयर कैपिटल अथवा वोटिंग राइट्स का जिक्र है। ये मंजूरी एक साल के लिए मान्य है। अगर इस बीच एलआईसी ने सौदे को पूरा नहीं किया, तो स्वीकृति समाप्त हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि आईसीआईसीआई बैंक से पहले एलआईसी को देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। 19 अगस्त को बैंक की नियामक फाइलिंग के अनुसार रिजर्व बैंक ने एलआईसी को एचडीएफसी बैंक की पेड-अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स का 9.99 फीसदी तक अधिग्रहण करने की अनुमति दी थी। फाइलिंग के आंकड़ों के अनुसार एलआईसी के पास पहले से ही बैंक की कुल शेयर पूंजी का 4.11 फीसदी हिस्सा मौजूद था।

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद का ध्वस्तीकरण अत्यंत निराशाजनक: अरशद मदनी

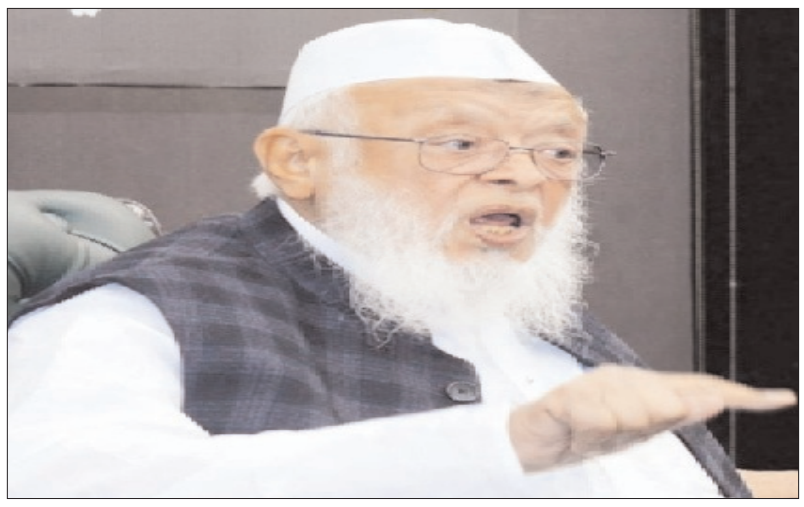

नई दिल्ली,एजेंसी। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित प्राचीन मस्जिद को ध्वस्त किए जाने पर गहरा दुख और निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना ने एक बार फिर देश के सामने यह बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संविधान और कानून का पालन वास्तव में हर नागरिक और हर धर्म के लिए समान है? अगर संविधान सभी को बराबरी का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और कानून का समान संरक्षण देता है तो उसको वास्तविक तौर पर लागू करने में यह दोहरा मापदंड क्यों दिखाई देता है? मौलाना मदनी ने कहा कि सहारनपुर की घटना सिर्फ एक मस्जिद का मामला नहीं है, बल्कि यह संविधान की सर्वोच्चता, कानून के शासन, धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिक समानता और राज्य की निष्पक्ष भूमिका से जुड़ा हुआ एक अत्यंत संवेदनशील मामला है।

उन्होंने कहा कि 1991 में जो पूजा स्थल अधिनियम लाया गया था, वह अभी मौजूद है, प्रशासन की यह कार्रवाई न केवल उस अधिनियम का उल्लंघन है बल्कि जो नया वक्फ कानून लाया गया है, उसमें वक्फ बाई यूजर की धारा की भी इस कार्रवाई से खुला उल्लंघन होता है और मस्जिद का वक्फ बोर्ड में पंजीकरण है, जिसका नंबर 451 है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जमीन शुरू से ही याकूब खान और वहीद खान के नाम से है, इसके बावजूद कार्रवाई किस न्याय के अंतर्गत है? उन्होंने कहा कि 'अगर अवैध कब्जा और अतिक्रमण ही कार्रवाई का एकमात्र मापदंड है तो फिर यही मापदंड हर धर्म, हर वर्ग के लिए समान होना चाहिए, लेकिन इस तरह के बहानों और कारणों से एक विशेष समुदाय को ही निशाना बनाया जा रहा है। मौलाना मदनी ने यह सवाल भी किया कि अगर देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी जमीनों, सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और दूसरी जगहों पर वर्षों और दशकों से धार्मिक निर्माण मौजूद हैं तो क्या इन सभी निर्माणों के खिलाफ भी प्रशासन इसी जल्दबाजी, इसी सख्ती और इसी मापदंड से कार्रवाई कर रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसी एक धार्मिक स्थल के मामले में असाधारण सख्ती न्याय के सिद्धांत पर सवाल खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि किसी धार्मिक स्थल की मिल्कियत या जमीन से संबंधित कानूनी विवाद को अदालत में तय किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय से जारी धार्मिक उपयोग, ऐतिहासिक दस्तावेजों और जमीनी तथ्यों को भी कानून के दायरे में पूरी गंभीरता से देखा जाना चाहिए। हमारा सवाल बिल्कुल सीधा है, जो कानून मस्जिद के लिए है, वही कानून हर धार्मिक स्थल के लिए क्यों नहीं है? जो मापदंड एक मुसलमान के लिए है, वही दूसरे नागरिक के लिए क्यों नहीं है? अगर संविधान और कानून सबके लिए हैं तो उसका संरक्षण और लागू करने में भी सबके लिए समान होना चाहिए।

योगी सरकार ने ताइवान की टेक कंपनियों को दिया यूपी में निवेश का न्योता

लखनऊ,एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत प्रौद्योगिकी के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने ताइपे में 02 से 04 सितंबर तक आयोजित 'सेमिकॉन 2026' में प्रमुख ताइवानी टेक कंपनियों के समक्ष राज्य में निवेश की संभावनाओं को प्रस्तुत किया और उन्हें सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

योगी सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियों, तैयार औद्योगिक बुनियादी ढांचे, कुशल मानव संसाधन और तेजी से विकसित हो रहे इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को ताइवानी कंपनियों के सामने प्रमुख ताकत के रूप में रखा गया। राज्य ने चिप निर्माण, सेंसर, डाटा सेंटर और सप्लाई चेन के स्थानीयकरण आदि क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी और निवेश के अवसरों पर जोर दिया। प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी आलोक कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने इंडिया-ताइवान सेमीकंडक्टर फोरम में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल में इन्वेस्ट यूपी की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेरणा शर्मा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनीष मीना शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने क्रिएटिव सेंसर्स इंक के चेयरमैन यूजीन हुआंग और कंपनी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक कर भारत में कंपनी के विस्तार की योजनाओं पर चर्चा की। इसके अलावा मीडियाटेक, एडीएटीए टेक्नोलॉजी और टीआईबीए बिजनेस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी निवेश, संयुक्त उपक्रम और दीर्घकालिक सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत हुई। आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए राज्य के औद्योगिक बुनियादी ढांचे, प्रगतिशील प्रोत्साहन नीतियों, कुशल कार्यबल और मजबूत टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने की योजनाओं की जानकारी दी। ताइवानी कंपनियों को सेंसर मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, परीक्षण और सप्लाई चेन के व्यापक स्थानीयकरण में निवेश के अवसरों से अवगत कराया गया।

गांवों की जरूरत के अनुरूप बने विकास की ठोस कार्ययोजना: आयुक्त सिन्हा

धमतरी,एजेंसी। गांवों की वास्तविक जरूरतों को केंद्र में रखकर विकास कार्यों की ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए और ऐसी गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हो, जिनका लाभ ग्रामीणों को लंबे समय तक मिल सके। यह बात विकसित भारत-जी राम जी के आयुक्त एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा ने शनिवार को विकासखंड कुरूद की विभिन्न ग्राम पंचायतों के भ्रमण के दौरान कही। उन्होंने शासन की योजनाओं और विकास कार्यों का मैदानी निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता, उपयोगिता और समयबद्ध क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

भ्रमण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जयंत नाहटा सहित पंचायत विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। आयुक्त सिन्हा ने ग्राम पंचायत धूमा में बालिका शौचालय निर्माण, अमृत सरोवर एवं पंचायत भवन का निरीक्षण किया, जबकि ग्राम पंचायत चरमुड़िया स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पौधरोपण भी किया। धूमा में बालिका शौचालय निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने निर्माण में लगे श्रमिकों से सीधे संवाद किया और मजदूरी भुगतान की स्थिति जानी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रमिकों से जुड़े भुगतान की आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के साथ श्रमिकों के हितों और उन्हें समय पर मजदूरी भुगतान का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अमृत सरोवर का निरीक्षण किया तथा स्व-सहायता समूह द्वारा की जा रही मछली पालन गतिविधियों की जानकारी ली। समूह के सदस्यों से आय, आजीविका और गतिविधियों की प्रगति पर चर्चा करते हुए उन्होंने जल संरक्षण से निर्मित परिसंपत्तियों को ग्रामीण आजीविका से जोड़ने तथा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। पंचायत भवन में क्यूआर कोड स्कैन कर उन्होंने ग्राम पंचायत में पूर्ण एवं प्रगतिरत विकास कार्यों की डिजिटल जानकारी देखी। उन्होंने क्लार्ट ऐप और युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तावित एवं स्वीकृत कार्यों की स्थिति की समीक्षा की तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों और निर्माण की प्रगति की जानकारी पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक से ली। उन्होंने अधिकारियों को पंचायत स्तर पर योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने, पोर्टल पर कार्यों की प्रगति समय-समय पर अपडेट करने और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल माध्यमों के प्रभावी उपयोग से योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।

धान खरीद के लिए पंजाब कैबिनेट की तीन नीतियों को मंजूरी, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लिए बड़े फैसले

चंडीगढ़,एजेंसी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में खरीफ मंडीकरण सीजन 2026-27 के दौरान धान की सुचारू खरीद और ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए तीन महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, कैबिनेट ने पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी फॉर खरीफ 2026-27, पंजाब फूडग्रेन्स ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी 2027 और पंजाब फूडग्रेन्स लेबर एंड कार्टेज पॉलिसी 2027 को स्वीकृति दी। सरकार ने आगामी धान खरीद सीजन में किसानों के एक-एक दाने की खरीद और लिफ्टिंग सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार नीतियों में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार भी मुख्यमंत्री को दिया गया है। कैबिनेट ने पंजाब लोक सेवा आयोग (ग्रुप 'ए') सेवा नियम, 2012 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके बाद आयोग में निजी सहायक से निजी सचिव पद पर पदोन्नति का प्रावधान शामिल करने का रास्ता साफ होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कैबिनेट ने सब-डिविजनल अस्पताल, चमकौर साहिब में 33 पदों के सृजन को मंजूरी दी। इनमें मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, नेत्र रोग, रेडियोलॉजी और एमबीबीएस जनरल के मेडिकल ऑफिसर के अलावा नर्सिंग सिस्टर, स्टाफ नर्स, सीनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ओटीए, ड्राइवर और क्लर्क सहित अन्य पद शामिल हैं।

इसके अलावा सिविल सर्जन कार्यालय, मालेरकोटला के लिए विभिन्न कैडरों के 19 नए पद सृजित किए जाएंगे। वहीं सब-डिविजनल अस्पताल धूरी और वहां बने नए एमसीएच सेंटर के लिए 119 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर (डेंटल) के 80 रिक्त पद भरने का फैसला भी लिया। इनमें 53 पद एक वर्ष से अधिक समय से, जबकि 27 पद एक वर्ष से कम अवधि से खाली हैं। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से धान खरीद व्यवस्था को सुचारू बनाने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को भी मजबूती मिलेगी।

छत्तीसगढ़: एआई के युग में शिक्षक बनें विद्यार्थियों के मार्गदर्शक, तकनीक के विवेकपूर्ण उपयोग की दें सीख- राज्यपाल रमेन डेका

रायपुर,एजेंसी। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिक्षक दिवस के अवसर पर लोकभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम् में आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मानित कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। समारोह में वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के 63 उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चार उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने वर्ष 2026-27 के राज्य शिक्षक सम्मान के लिए चयनित 64 शिक्षकों के नामों की घोषणा भी की।

समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा और शिक्षक की भूमिका भी व्यापक हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस दौर में शिक्षकों और विद्यार्थियों का नई तकनीकों से परिचित होना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी तकनीक का विवेकपूर्ण, जिम्मेदार और मानवीय मूल्यों के अनुरूप उपयोग है। उन्होंने कहा कि एआई हमारा सहायक बने, हमारा नियंत्रक नहीं। शिक्षक विद्यार्थियों को तकनीक का उपयोग ज्ञान अर्जित करने, नवाचार करने और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए प्रेरित करें। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि, आज गूगल और डिजिटल तकनीक के माध्यम से हमारे पास सूचनाओं का विशाल संसार उपलब्ध है। इसके बावजूद हमें यह ध्यान रखना होगा कि तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता स्वतंत्र चिंतन और बौद्धिक विकास को प्रभावित न करे। दुनिया के अनेक देशों में विद्यार्थियों द्वारा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर गंभीर विचार-विमर्श हो रहा है। तकनीक हमें जानकारी उपलब्ध करा सकती है, लेकिन संस्कार, संवेदना, अनुशासन, प्रेरणा और जीवन की सही दिशा गुरु से ही मिलती है। इसलिए बदलते समय में शिक्षक की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक, कौशल आधारित, बहुभाषी और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार किया है। आने वाले समय में शिक्षा के स्वरूप में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में शिक्षकों को निरंतर अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करना होगा। साथ ही विद्यार्थियों की रुचि और प्रतिभा को पहचानकर उन्हें सही विषय और करियर चुनने में मार्गदर्शन देना होगा। विद्यार्थियों की काउंसलिंग भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका का हिस्सा है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षण केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक महान और गरिमामय दायित्व है। शिक्षक अपने ज्ञान के साथ-साथ अपने आचरण से भी विद्यार्थियों को शिक्षित करते हैं। बच्चे अपने शिक्षकों को आदर्श के रूप में देखते हैं, इसलिए शिक्षकों को अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ निर्वहन करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी कैसे आगे बढ़े, उसकी प्रतिभा कैसे निखरे और उसका भविष्य कैसे बेहतर बने, यह शिक्षक की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियां साझा करते हुए राज्यपाल डेका ने कहा कि शिक्षक दिवस उन्हें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की अपनी यात्रा की याद दिलाता है। पहले शिक्षक और विद्यार्थी के बीच आदर, आत्मीयता और विश्वास का अत्यंत गहरा संबंध होता था। सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षक पूरी सेवा भावना और समर्पण के साथ विद्यार्थियों का भविष्य संवारते थे।

यही समर्पण और आत्मीयता शिक्षक-विद्यार्थी संबंध की वास्तविक शक्ति है। राज्यपाल डेका ने शासकीय सेवा में स्थानांतरण को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताते हुए कहा कि जहां भी दायित्व मिले, उसे सहजता से स्वीकार कर पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने सम्मानित सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के शिक्षक अपने ज्ञान, अनुभव और समर्पण से छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजनों को शुभकामनाएं दीं और राज्यस्तरीय सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान शिक्षकों के समर्पण, कठिन परिश्रम, नवाचार और विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों का सम्मान है।

अडाणी डिफेंस और इंडो-रशियन राइफल्स ने एके-203 के लिए गोला-बारूद की सप्लाई के लिए पांच साल का समझौता किया

नई दिल्ली,एजेंसी। अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (आईआरआरपीएल) ने भारतीय सशस्त्र बलों की आधुनिक एके-203 असॉल्ट राइफल के लिए गोला-बारूद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को पांच साल का ऐतिहासिक समझौता किया है।

कंपनी ने जारी बयान में बताया कि अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पांच साल का एक समझौता किया है। समझौते के तहत अडाणी डिफेंस पांच साल तक एके-203 के लिए 7.62×39 मिमी गोला-बारूद की सप्लाई करेगी। इस समझौते से आईआरआरपीएल द्वारा एके-203 राइफल का उत्पादन और अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के द्वारा गोला-बारूद का उत्पादन एक साथ आ गया है, जिससे भारत में एक इंटीग्रेटेड सप्लाई की चेन बन रही है। ये समझौता इस प्रोग्राम के लिए स्वदेशी 7.62×39 मिमी छोटे कैलिबर वाले गोला-बारूद की सप्लाई के लिए किया गया है। आईआरआरपीएल भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर है, जो कि भारत में एके-203 असॉल्ट राइफल बनाता है। अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड को 2019 में भारत-रूस के बीच सरकारी समझौते के तहत भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एके-203 असॉल्ट राइफल बनाने के लिए किया गया था। इसकी निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरवा में स्थित है। अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस कंपनी ने भारत में छोटे कैलिबर वाले गोला और बारूद के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं विकसित की हैं, जिसमें कानपुर में एक ऐसी सुविधा भी शामिल है जहां छोटे कैलिबर वाले गोला-बारूद का उत्पादन भी किया जा सकता है। यह समझौता छोटे हथियारों की सप्लाई चेन में घरेलू क्षमताओं को और मजबूत करता है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को बढ़ावा देता है।

उल्लेखनीय है कि इस ज्वाइंट वेंचर में भारतीय शेयरधारक 'एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड' और 'म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड' हैं। इसके साथ ही रूसी शेयरधारक 'कंसर्न कलाशिनकोव' और 'रोसोबोरोनएक्सपोर्ट' हैं। यह व्यवस्था प्रोग्राम के लिए ज़रूरी गोला-बारूद का भारतीय स्रोत उपलब्ध कराती है और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान सप्लाई को लगातार बनाए रखने में मदद करती है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)